



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2006/फाल्गुन 9, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2006/PHALGUNA 9, 1927

वित्त भंग्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2006

बजट 2006-2007

वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम का भाषण

28 फरवरी, 2006

भाग-क

अध्यक्ष महोदय,

फा. सं. 2(16)-बी(डी)/2006.—मैं वर्ष 2006-2007 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

I. अर्थव्यवस्था का पर्यावलोकन

2. बीस महीने पहले, जब मैंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया था, तो मैंने माननीय सदस्यों और इस देश के सभी लोगों का सम्मान और साहस के मार्ग पर हमारे साथ चलने का आहवान किया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार (यू.पी.ए.) के पहले वर्ष के कार्य निष्पादन की अन्तिम रिपोर्ट निकल चुकी है और इस पर प्रसन्नता व्यक्त की जा सकती है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) के अनुसार वर्ष 2004-05 में वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी जिसमें विनिर्माण क्षेत्रक की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान बाजार मूल्यों पर, सकल घरेलू बचतों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 29.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और सकल पूँजी निर्माण की दर बढ़कर जी.डी.पी. का 30.1 प्रतिशत हो गई। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इन परिणामों के पीछे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) द्वारा दिया गया राजनैतिक संदेश; प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का दूरदर्शी नेतृत्व; सरकार द्वारा किये गये नीतिगत परिवर्तन और भारतीय जनता का यह अटूट विश्वास है कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

3. मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2005-06 की संभावनाये अच्छी हैं भले ही बेहतर न हों। इस वर्ष को सबसे अच्छा और सबसे बुरा वर्ष कहा जा सकता है। प्रकृति की हम पर कृपा नहीं रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने फसलों, सड़कों, मकानों और आधार संरचनाओं की अत्यधिक क्षति के साथ साथ भारी संख्या में मानव जीवन का संहार किया। सरकार ने तुरंत अंतरिम राहत प्रदान की और इसके साथ साथ केन्द्रीय आरक्षित निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय

आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से आज तक कुल 5145.37 करोड़ रुपये प्रदान किये गए हैं। स्पष्टतः यह सहायता पर्याप्त नहीं होगी। योजना आयोग क्षतिग्रस्त आधार संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिये एक कार्यक्रम तैयार करेगा, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये धन प्रदान करेगी।

4. यह सबसे अच्छा समय भी था। सरकार उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित करने के एन.सी.एम.पी. के पहले दायित्व को पूरा करने में समर्थ रही है। सी.एस.ओ. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस वर्ष जी.डी.पी. की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत होने की संभावना है जिसमें विनिर्माण क्षेत्रक की वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत होने की आशा है। कृषि वृद्धि दर पुनः 2.3 प्रतिशत पर आ गई है और खनन को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रकों का निष्पादन संतोषजनक है। 11 फरवरी, 2006 को मुद्रारफीति 4.02 प्रतिशत थी। गैर-खाद्य ऋण में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है। इसका अधिकांश श्रेय हमारे किसानों, कामगारों, सेवा प्रदायकों, व्यापारियों और कारोबारियों को जाता है और उनका सम्मान करने में मेरा साथ देने का मैं सदन से आग्रह करता हूँ।

5. गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार जारी है। मेरा विश्वास है कि गरीबी का सबसे अच्छा इलाज वृद्धि एवं विकास है। दसवीं योजना के लिये जी.डी.पी. वृद्धि लक्ष्य 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। तीन वर्षों में 7.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से यह संभव है कि समग्र वृद्धि दर 7 प्रतिशत होगी। प्रधान मंत्री ने अपने हाल के वक्तव्यों में यह सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत की है और सरकार इस उच्च वृद्धि की मंजिल तक देश को ले जाने के लिये कृत संकल्प है। वृद्धि हमारी मंजिल होगी; समानता हमारी सहचरी होगी; और सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य होगा।

II. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अधिदेश का कार्यान्वयन

6. इस वर्ष की हमारी यह सफलता बढ़े हुए राजस्वों और नियंत्रित व्यय के माध्यम से राजकोषीय विवेक पर हमारे द्वारा नियंत्रण जोर देने, मौद्रिक स्थायित्व और विदेशी ऋण प्रबंधन का परिणाम है। तथापि, हमारी सफलता के संतोष से हमें इस मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और हम ऐसा नहीं होने देंगे।

7. एन.सी.एम.पी. का एक महत्वपूर्ण दायित्व था कृषि पर ध्यान केन्द्रित करना: हमने ऐसा किया है और खाद्यान उत्पादन 209.3 मिलियन टन होने की आशा है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 मिलियन टन अधिक है।

8. एन.सी.एम.पी. का अधिदेश रोजगार को बढ़ावा देना है: गरीबों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिये उत्पादक क्षेत्रकों में स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करते हुए 2 फरवरी, 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शुरू की गई। चालू वर्ष में काम के बदले अनाज कार्यक्रम सहित अनेक स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार के लिये 11,700 करोड़ रुपये की धनरांश खर्च करने की आशा है।

9. एन.सी.एम.पी. का अधिदेश सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने का है; निवेश की दर 2002-03 में 25.3 प्रतिशत से नियंत्रण बढ़ाकर 2004-05 में 30.1 प्रतिशत हो गई है। अनेक संकेतक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के नियंत्रण उछाल को प्रदर्शित करते हैं।

10. एन.सी.एम.पी. सरकार द्वारा आधार संरचनाएं बढ़ाने का भी अधिदेश देता है। वर्ष 2005-06 में विद्युत उत्पादन में 5,083 मेगावाट क्षमता बढ़ाई जाएगी और दसवीं योजना अवधि के दौरान कुल क्षमता वृद्धि 34,000 मेगावाट करने का अनुमान है जो एक रिकार्ड है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2005 तक 95 जिलों में यरियोजनाओं के लिये टेके दिये

गये हैं जिनके अंतर्गत 41,461 अविद्युतीकृत और 9,379 विद्युतीकृत गांव शामिल हैं। स्वर्ण चतुर्भुज (जी.क्यू.) और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारों (कारिडोसी) पर पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। मई 2004 से पूर्व पूर्ण 1.86 किमी. प्रतिदिन की तुलना में, योजनाये 4.48 किमी. प्रतिदिन की गति से बढ़ रही हैं। जून, 2006 तक 96 प्रतिशत जी.क्यू. पूरे कर लिये जायेंगे और 2008 के अंत तक गलियारे पूर्ण हो जायेंगे। हमारे पत्तनों, विमानपत्तनों और ग्रामीण सड़कों का सुधार कार्य भी पर्याप्त रूप से प्रगति पर है।

11. वर्ष की समाप्ति तक मैं संतोष के साथ यह कह पाऊंगा कि हमने आम आदमी को जो वचन दिये थे उन्हें पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया गया है।

III भारत निर्माण

12. मैं भारत निर्माण का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। यह प्रशासन में यू.पी.ए. की कार्यप्रणाली का प्रतीक है। यह परिवर्तन का ऐसा उदाहरण है जिससे हम वृद्धि से प्राप्त संसाधनों का उपयोग आधार संरचनाओं के निर्माण और ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के लिये कर सकेंगे। माननीय सदस्य भारत निर्माण के छः घटकों और वर्ष 2009 तक प्राप्त किये जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से अवगत हैं। इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष 2005-06 में:-

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत अब तक अनुदान के रूप में 944.18 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं और इस वर्ष 600,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है।
- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत 56,270 आवासों के भौतिक लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2006 तक 47,546 आवासों को इसमें लाया जा चुका है।
- ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत सितम्बर, 2005 तक 5,337 आवासों को जोड़ा गया और अभी तक 3,749 करोड़ रुपये रिलीज कर दिये गये हैं।
- जनवरी, 2006 तक 870,000 ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है और 2,260 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 1,100 करोड़ रुपये के संपूर्ण आबंटन की धनराशि रिलीज कर दी गई है और 10,366 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की आशा है।
- तीन वर्षीय कार्यक्रम के पहले वर्ष में दिसम्बर, 2005 तक 17,182 गांवों को टेलीफोन प्रदान किये गये हैं।

जो भारत निर्माण का मजाक उड़ाते थे उनके लिये ये आंकड़े एक स्टीक उत्तर हैं। हम इस कार्यक्रम को भिशन के रूप में चलाने और निष्पादित करने के प्रति दृढ़-संकल्प हैं। चूंकि भारत निर्माण के कार्यान्वयन ने गति पकड़ ली है, अतः मैं इस कार्यक्रम के लिये अधिक बजटीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। पूर्वोत्तर घटक सहित चालू वर्ष में प्रदान किये गये 2,160 करोड़ रुपये की तुलना में 2006-07 के लिये यह बजटीय प्रावधान 18,696 करोड़ रुपये का होगा जो 54 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

IV अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

13. अब मैं बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्पष्टतः, संसाधनों का बढ़ा हिस्सा यू.पी.ए. सरकार के आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों अर्थात् सर्वशिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन रकीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, संपूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को जाना चाहिए।

14. वर्ष 2005-06 में योजना के लिये सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) 143,497 करोड़ रुपये की थी। इसमें से केन्द्रीय योजना को सहायता 110,385 करोड़ रुपये की थी। मैं दोनों आबंटनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2006-07 के लिये जी.बी.एस. 172,728 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 20.4 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें से केन्द्रीय योजना को 131,285 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।

15. शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता जारी रहेगी। वर्ष 2006-07 के लिए शिक्षा में आवंटन 31.5 प्रतिशत बढ़ाकर 24,115 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 22.0 प्रतिशत बढ़ाकर 12,546 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

16. आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये 2005-06 में कुल आवंटन की धनराशि 34,927 करोड़ रुपये थी। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल आवंटन 50,015 करोड़ रुपये का होगा जो 15,088 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि या 43.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.)

17. परन्तु हमें इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के लिये स्कीमों और कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के आयोजना बजट का 10 प्रतिशत आवंटन जोड़ना चाहिए। अकेले फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिये 2006-07 में यह 4,870 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के समान होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये कुल बजट आवंटन 12,041 करोड़ रुपये है जिसमें 1,350 करोड़ रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डी.ओ.एन.ई.आर.) को दी गई थी। बजट अनुमान 2005-06 की तुलना में बजट अनुमान 2006-07 में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

सर्व शिक्षा अभियान

18. सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) ने नये विद्यालयों, अतिरिक्त अध्ययन कक्षों और अतिरिक्त अध्यापकों के संदर्भ में 2005-06 में उल्लेखनीय प्रगति की है। दो ख्यतंत्र सर्वेक्षण यह प्रदर्शित करते हैं कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 93 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं और विद्यालय न आने वाले बच्चों-की संख्या कम होकर लगभग एक करोड़ रह गई है। इस अच्छे निष्पादन को देखते हुए मैं 2006-07 में एस.एस.ए. के लिये यह परिव्यय 7,156 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,041 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। 5,00,000 अतिरिक्त अध्ययन कक्षों का निर्माण किया जाएगा और 150,000 अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

19. वर्ष 2006-07 में हम शिक्षा उपकर के माध्यम से जुटाये गये राजस्व से 8,746 करोड़ रुपये प्रारंभिक शिक्षा कोष में हस्तांतरित करेंगे।

मध्याह्न भोजन स्कीम

20. मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत अब 12 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है जो विश्व में सबसे बड़ा "स्कूल लंच" कार्यक्रम है। मैं आवंटन 3,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 4,813 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

पेयजल एवं सफाई

21. पेयजल के चालू वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और 56,270 आवासों और 140,000 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। शामिल न किये जाने के अलावा चूक हो जाने की निरंतर समस्या होती है। दोनों समस्याओं के समाधान की कार्यनीति में संक्षण, बेहतर प्रचालन प्रबंधन और जल गुणवत्ता मानिटरिंग तथा ग्रामीण स्तर पर क्षमता निर्माण शामिल है। जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और फील्ड स्तरीय पेयजल किटों के लिये सरकार 2006-07 में 213 करोड़ रुपये की अनावर्ती सहायता प्रदान करेगी। मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिये प्रावधान 3,645 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 4,680 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

22. मैं ग्रामीण सफाई अभियान के लिये प्रावधान 630 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 720 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

23. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। मुझे विश्वास है कि 2006-07 में 200,000 से अधिक सहयोगी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एस.एच.ए.) पूर्ण रूप से कार्यरत हो जायेंगे और 1,000 से अधिक द्वाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दिन रात सेवायें प्रदान करेंगे। मैंने एन.आर.एच.एम. के लिये आवंटन 6,553 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिये 8,207 करोड़ रुपये कर दिया है।

24. "कुष्ठ रोग उन्मूलन" को परिभाषित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक प्रति 10,000 की आबादी पर एक मामला है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य दिसम्बर, 2005 में प्राप्त कर लिया गया है। उत्साहजनक टीकाकरण कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आशा करते हैं कि दिसम्बर, 2007 तक देश से पोलियो का भी सफाया हो जाएगा।

एकीकृत बाल विकास सेवायें

25. हमने एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम का विस्तार किया है और 188,168 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की है। पूरक पोषाहार इस स्कीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। इस वर्ष से शुरू करते हुए केन्द्र सरकार पूरक पोषाहार के लिये राज्यों को किये गये वार्ताविक व्यय के 50 प्रतिशत या लागत मानदण्डों के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष केन्द्र सरकार की यह लागत 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, और वर्ष 2006-07 के लिये मैं यह सहायता बढ़ाकर 1,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। आई.सी.डी.एस. के लिये कुल आवंटन 3,315 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,087 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एन.आर.ई.जी.)

26. मैंने ग्रामीण रोजगार स्कीम का उल्लेख किया है जो ग्रामीण बेरोजगारी और भुखमरी से लड़ने का मुख्य साधन है। वर्ष 2006-07 में ग्रामीण रोजगार के लिए कुल आवंटन 14,300 करोड़

रुपये का होगा। इसमें से 11,300 करोड़ रुपये (एनईआर घटक सहित) एन.आर.ई.जी. अधिनियम के अंतर्गत होंगे और 3,000 करोड़ रुपये (एनईआर घटक सहित) एसजीआरवाई के अंतर्गत होंगे। चूंकि एनआरईजी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार की वैधानिक गारंटी है अतः आवश्यकता के अनुसार अधिक निधियां प्रदान की जाएंगी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

27. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 3 दिसम्बर, 2005 से शुरू किया गया था। अगले वर्ष के लिये 6,250 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय में 4,595 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। मुंबई मेट्रो रेल और बंगलौर मेट्रो रेल सहित, जिनका मैंने अपने पिछले बजट में उल्लेख किया था, चार परियोजनाओं के अलावा जो परियोजनायें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं उनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात की परियोजनायें शामिल हैं।

28. वृद्धि रोजगार एवं बेहतर जीवन दशा के लिये नियोजित शहरीकरण प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। सरकार नये नगरों की स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती, विशेषकर विशिष्ट उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, या विशिष्ट क्षेत्र जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुछ परियोजनायें तैयार की जा रही हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

29. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले गरीब व्यक्तियों को प्रतिमाह 75 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। यह एकदम अपर्याप्त है। मैं यह पेंशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने वर्ष 2006-07 के लिये 1,430 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है और वर्ष के दौरान यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएंगी। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वह अपने संसाधनों से समान अंशदान करें ताकि गरीब पेंशनर को प्रतिमाह कम से कम 400 रुपये मिल सकें। मैं डाक विभाग और बैंकों के साथ कार्य करने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि दो वर्ष के अंदर एक ऐसी प्रणाली स्थापित हो जाय जिसके अंतर्गत डाकघर या बैंक में लाभार्थी के खाते में पेंशन जमा हो सके।

महिलायें और बच्चे

30. पिछले वर्ष मैंने बजटीय आबंटनों की लिंग आधारित संवेदनशीलताओं पर प्रकाश डालते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया था। मैं 10 अनुदान मांगे शामिल कर सका। इस बार मैं ऐसी स्कीमों को शामिल करने के लिये लिंग आधारित बजट व्यवस्था पर विवरण बढ़ाने में सफल रहा हूं जहां 100 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के लाभ के लिये है और जहां स्कीमों में कम से कम 30 प्रतिशत आबंटन महिलाओं के लिये है। अब इस विवरण के अंतर्गत 18 मंत्रालयों/विभागों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों की 24 अनुदान मांगें और 28,737 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्कीमें शामिल हैं।

31. इसके अलावा अनेक मंत्रालयों और विभागों ने लिंग के परिप्रेक्ष्य में अपने बजट की लोक व्यय रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। 32 मंत्रालयों और विभागों ने लिंग आधारित बजट व्यवस्था कक्षों की स्थापना कर दी है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

32. सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति वचनवद्ध है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बजट में पिछले वर्ष की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की स्कीमों पर अलग से विवरण

दिया गया है। समान आधार पर केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के लिए आबंटन 14.5 प्रतिशत बढ़ाकर 2,902 करोड़ रुपये किया गया है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कम से कम 20 प्रतिशत आबंटन वाली स्कीमों के लिये आबंटन 13.9 प्रतिशत बढ़ाकर 9,690 करोड़ रुपये किया गया है।

33. वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में इकिवटी अंशदान बढ़ाकर 37 करोड़ रुपये किया जा रहा है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम में 80 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक

34. मैं अल्पसंख्यकों के कल्याण में सक्रियता से कार्य कर रहे संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, मेरी मंशा मौलाना आजाद शैक्षणिक फाउण्डेशन की निधि के कार्पस को दुगुना कर 200 करोड़ रुपये करने की है।

35. मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में 16.47 करोड़ रुपये के अंशदान प्रदान कर इसका इकिवटी आधार सुवृद्ध करने का प्रस्ताव करता हूं। 15 अगस्त, 2005 को प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसुप्त यह निगम शहरी और इसके आसपास के केन्द्रों में रहने वाले शिल्पियों और बुनकरों, विशेषकर अल्पसंख्यकों की अधिकता वाले जिलों में पहुंचकर अपने प्रयत्नों में तेजी लाएगा। कार्यक्रम में कौशल बढ़ाने, ऋण और तकनीकी-प्रबंधकीय सहायता पर जोर दिया जाएगा।

36. मैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद के लिये आबंटन 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

37. योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां छात्रों को उच्चतर अध्ययनों के लिये प्रोत्साहित करती हैं। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिये 20,000 ऐसी छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण करेगी। वर्ष 2006-07 में स्कीम को एक बार अंतिम रूप दिये जाने पर, मैं आवश्यक निधियां आंबंटित करने का विचार रखता हूं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम

38. वर्ष 2004 में शुरू की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के प्रारंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिये 1,000 नये आवासीय-विद्यालय खोले जायेंगे। मैंने 128 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है और वर्ष के दौरान 172 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिये मैं सहमत हूं। मैं ऐसी बालिका के लिये, जो आठवीं दर्जे की परीक्षा उत्तीर्ण करती है और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है, आगे और प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं। उसके नाम पर 3,000 रुपये की धनराशि रख दी जाएगी और 18 वर्ष की आयु होने पर वह इसे निकाल सकने की हकदार होगी।

39. सरकार ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक के कार्यक्रमों के परिणामों में केवल "मात्रा" से "गुणवत्ता" की दिशा में अधिक ध्यान देना शुरू किया है। सार्वजनिक व्यय के लिये भूल्य सुनिश्चित करने हेतु 25 अगस्त, 2005 को एक "आउटकम बजट" प्रस्तुत किया गया था। सरकार का इशाद बजट सत्र की समाप्ति से पहले प्रथम आउटकम बजट पर एक निष्पादन बजट प्रस्तुत करने का है। वर्ष 2006-07 का आउटकम बजट 17 मार्च, 2006 तक इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह नया प्रयास सही मात्रा और गुणवत्ता में लक्षित सेवायें आम आदमी को प्रदान करने के हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है।

V निवेश

40. देश में निवेश की तेजी आई है और निवेशकों के विश्वास को बनाये रखना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत, पूर्वी एशिया और चीन की उच्च निवेश दरों को प्राप्त कर रहा है। माननीय सदस्य इस समय यह पायेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रक में अधिक निवेश को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

41. सरकार सुदृढ़ और प्रभावशाली सरकारी क्षेत्रक के लिये बचनबद्ध है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पास आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों के जरिये 2006-07 के लिये 122,757 करोड़ रुपये की निवेश-योजनायें हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (रेलवे सहित) को 16,901 करोड़ रुपये की इकिवटी सहायता और 2,789 करोड़ संपर्ये के ऋण प्रदान करेगी। इसके अलावा मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हमने सरकारी क्षेत्र के दस उद्यमों के पुनर्गठन के लिये जिसमें भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड और भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड भी शामिल हैं, नकद रूप में 1,180 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और 2,566 करोड़ रुपये की गैर-नकदी न्यौछावर की है।

42. हमारा विश्वास है कि भारत को रत्न और आभूषण के उद्योग के एक केन्द्र के रूप में ग्रिकसित करने की काफी भुजाइश है। अतः मैं एक विशेषज्ञ निकाय गठित करने का प्रस्ताव करता हूं जो इस क्षेत्रक की संभावनाओं और भारत तथा विदेश में विद्यमान कराधान पद्धतियों की जांच करेगा और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। मुझे विश्वास है कि इस घोषणा का अनिवारी भारतीयों द्वारा स्वागत किया जाएगा जो भारत को भावी विस्तार एवं वृद्धि के स्थान के रूप में देख रहे हैं।

43. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। भारत को विश्व बाजार के लिये वस्त्र, आटोमोबाइल्स, इस्पात, धातुओं, पेट्रोलियम उत्पादों आदि के विनिर्माण का केन्द्र स्थान बनाने के हमारे पास अवसर हैं। कलैण्डर वर्ष 2005 में नवम्बर, 2005 तक 4 बिलियन डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अनुमान है जिसमें पुनर्निवेशित आय और अन्य पूँजी की गणना महीं की गई है। मुझे विश्वास है कि हाल के नीतिगत परिवर्तनों से देश में, विशेषकर आधार संरचना में, अधिक विदेशी निवेश होगा।

VI कृषि

44. अब मैं अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रकों की ओर आता हूं। हमेशा की तरह हमारी सरकार का मुख्य जोर कृषि पर है। आश्वासित सिंचाई, ऋण, विविधकरण और कृषि उत्पादों के लिये बाजार सृजित करना हमारे मुख्य क्षेत्र हैं।

सिंचाई

45. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत 2005-06 में 4,500 करोड़ रुपये के परिव्यय में से अनुदान के रूप में 1,680 करोड़ रुपये दिये गये। राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से 2,520 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की आशा है और वर्ष के अंत से पहले 25 परियोजनाएं पूरी होने की आशा है। वर्ष 2006-07 के लिए परिव्यय बढ़ाकर 7,121 करोड़ रुपये कर दिया गया है और केन्द्र सरकार 2,350 करोड़ रुपये के अनुदान के माध्यम से कार्यक्रम को सहायता देगी। जल संसाधन मंत्रालय जल उपयोगकर्ता संघों से माध्यम के भागीदारीपूर्ण सिंचाई के लिये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करेगा।

46. जल निकायों की मरम्मत, नदीकरण और पुनर्बहाली कार्यक्रम का कार्यान्वयन 13 राज्यों के 23 जिलों में प्रायलट परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। राज्यों के परामर्श से कार्यक्रम के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले चरण में 1.47 मिलियन हेक्टेयर के कमान क्षेत्र चरण में 20,000 जल निकायों की पहचान कर ली गई है। इसकी अनुमानित लागत 4,481 करोड़ रुपये है। निधि पोषण प्रणाली (केन्द्र, राज्य और विदेशी सहायता) को अंतिम रूप दे दिया गया है और मेरा बहु-पक्षीय एजेंसियों से निधियां मांगने और प्राप्त करने का विचार है। भागीदार राज्य सरकार से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा और उस राज्य के जल निकायों को 2006-07 में मरम्मत, नदीकरण और पुनर्बहाली के लिये किया जाएगा।

ऋण

47. वर्ष 2004-05 में फार्म ऋण बढ़कर 125,309 करोड़ रुपये (लक्ष्य से काफी ऊपर) किया गया और इसके चालू वर्ष के लिये निर्धारित 141,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पुनः पार करने की आशा है। मैं 2006-07 में ऋण स्तर बढ़ाकर 175,000 करोड़ रुपये करने और अपने पोर्टफोलियो में अन्य 50 लाख किसानों को शामिल करने के लिए बैंकों से अनुरोध करने का प्रस्ताव करता हूं। हम तीन वर्षों में कृषि ऋण प्राप्त ही नहीं करेंगे बल्कि इसको दुगुना करने के लक्ष्य से भी आगे बढ़ जायेंगे। चूंकि काश्तकार किसानों को पर्याप्त रूप से लाभ नहीं मिलता अतः मैंने काश्तकार किसानों के स्व-सहायता समूहों या संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों के लिए अलग खिड़की खोलने और उन्हें कुल ऋण का एक निर्धारित हिस्सा देना सुनिश्चित करने के लिये बैंकों से कहा है। मैं इस संबंध में हुई प्रगति की बारीकी से मॉनिटरिंग करने का इरादा रखता हूं।

48. पिछले दो वर्षों में किसानों के सामने आई गंभीर कठिनाइयों की मुझे जानकारी है। हमारी सरकार दयालु है। मेरे सामने गंभीर राजकोषीय कठिनाईयां भी हैं। मैं किसी दुविधा की स्थिति में अधिकतर अपने प्रिय कवि-दार्शनिक, संत तिरुवल्लूर का सहारा लेता हूं। 2000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा था:

"कर्मम सिध्यमल कन्नोडा वल्लार्कु
उरिमई उद्ययदु इव उलगु"

(यह संसार उसका है जो अपना कार्य दयालु भाव से करता है)

मैं हमारे किसानों की सहायता के लिए और भी अधिक सहयोग करने को तैयार हूं। इसकी शुरुआत करते हुए मैं उन किसानों को कुछ राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आर.आर.बी. और पी.ए.सी.एस. से खरीफ और रबी, 2005-06 के लिये फसल ऋण लिया है। तबनुसार 1,00,000 रुपये तक के मूल धन पर ऋणकर्ता के ब्याज की देनदारी के दो प्रतिशत प्वाइंट के बराबर धनराशि 31 मार्च, 2006 से पहले उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मैंने 1,700 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। मुझे आशा है यह सदन सरकार के इस विशेष प्रयास का स्वागत करेगा।

49. हमारे किसानों के लिए मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। किसान सहकारी ऋण संरचना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से अल्पावधिक ऋण प्राप्त करते हैं, जिसका नाबाड़ से पुनर्वित्त पोषण किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी किसानों को अधिकाधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। मेरा इरादा यह सुनिश्चित करने का है कि "नाबाड़" तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को किफायती दर पर पुनर्वित्त ऋण देना जारी रखे ताकि किसान को उचित दर पर ऋण

मिल सके। तदनुसार बाजार के हालात पर ध्यानपूर्वक विचार करके सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर अल्पावधिक ऋण मिल सके जिसकी मूलधन पर अधिकतम सीमा 3,00,000 रुपये हो। इसके लिये "नाबार्ड" को कुछ स्तर तक आर्थिक सहायता की जरूरत होगी। मैं आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं। यह नीति खरीफ 2006-07 से लागू होगी तथा मैं उचित समय पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूंगा।

50. ग्रामीण आधार संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) ने अभी तक 11 किलोमीटर में निधियां वितरित की हैं। आर.आई.डी.एफ. XI की स्वीकृतियां 31 जनवरी, 2006 तक 7,301 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई हैं। इस वर्ष की स्वीकृतियां की एक विशेषता यह है कि 346 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों को स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष के अंत तक इस धनराशि के 600 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। ग्रामीण आधार संरचना के सृजन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं आर.आई.डी.एफ. XII का कार्पस बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं और राज्य सरकारों से इन निधियों का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

51. मैं आर.आई.डी.एफ. निधियों तक पहुंच के लिये सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) माडल के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की स्वीकृति का भी प्रस्ताव करता हूं।

52. भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के लिये बड़ी निधियों की आवश्यकता है। अतः मैं ग्रामीण सड़कों के लिये वर्ष 2006-07 के दौरान आर.आई.डी.एफ. XII के अधीन 4,000 करोड़ रुपये के कार्पस से एक अलग खिड़की खोलने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि बीमा

53. राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) को खरीफ और रबी 2006-07 के लिये इसके वर्तमान रूप में ही जारी रखा जाएगा।

बागान क्षेत्रक

54. चाय के बड़े पैमाने पर पौधारोपण और उसे पुनः उगाने के लिये 15-वर्षीय कार्यक्रम शुरु करने की पिछले बजट की घोषणा के क्रम में वाणिज्य मंत्रालय ने एक विशेष प्रयोजनी चाय निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके ब्यारे तैयार किये जा रहे हैं परन्तु इस विचार को अपना समर्थन देने के लिये मैं इस निधि में प्रतिवर्ष लेवीयुक्त अंशदान का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2006-07 के लिये यह अंशदान 100 करोड़ रुपये होने की आशा है। इसकी स्थापना हो जाने पर यह निधि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तरांचल राज्यों सहित चाय उत्पादक राज्यों में उत्पादकों को लाभ प्रदान करेगी।

सूक्ष्म-वित्त

55. मैंने पिछले बजट में सूक्ष्म वित्त के संबंध में बड़ी पहले करने का प्रस्ताव किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकिंग संवाददाता और बैंकिंग एजेंटों की नियुक्ति के लिये मार्ग-निर्देश जारी कर दिये हैं। ई.सी.बी. निधियों तक पहुंचने के लिये एक खिड़की भी खोल दी गई है। सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक के संवर्धन, विकास और विनियमन के लिये एक औपचारिक सांविधिक ढांचा प्रदान करने हेतु इस सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

56. रव-सहायता समूह (एस.एच.जी.) आन्दोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। यू.पी.ए. सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हमने 801,000 रव-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ा है। इन रव-सहायता समूहों को वितरित ऋण की धनराशि लगभग 4,863 करोड़ रुपये है। मैं वर्ष 2006-07

में अन्य 385,000 एस.एच.जी. को ऋण संबद्ध करने के लिये बैंकिंग क्षेत्रक से अनुरोध करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं एस.एच.जी. के माध्यम से फार्म उत्पादन के वित्त पोषण और निवेश-क्रियाकलापों हेतु अलग ऋण-लाइन खोलने का "नाबार्ड" से भी आग्रह करूंगा।

57. एनएसएस के 59वें चक्र (2003) के निष्कर्षों से पता चलता है कि कुल किसान परिवारों में से केवल 27 प्रतिशत को ही विधिवत् स्रोतों से तथा 22 प्रतिशत किसान परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त होता है। शेष परिवारों, जो मुख्यतः छोटे तथा सीमांत किसान हैं, की वास्तव में ऋण तक पहुंच हो ही नहीं पाती। अधिक किसान परिवारों को बैंकिंग दायरे में शामिल करने के लिए, मैं एक वित्तीय समावेश समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समिति से किसान परिवारों के ऋण सुविधा दायरे से बाहर रहने के कारणों का पता लगाने तथा ऋण देने वाले संस्थानों से ऋण चाहने वाले प्रत्येक किसान परिवार के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी योजना तैयार करने संबंधी सुझाव देने के लिए कहा जाएगा।

बागवानी तथा मछली पालन

58. देश के विभिन्न भागों के आदर्श टर्मानल बाजार स्थापित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए 2006-07 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। नागार्लैंड में एक केन्द्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना की जाएगी। शीघ्र ही राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

VII विनिर्माण

रोजगार

59. विनिर्माण तथा सेवा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने की क्षमता है। विनिर्माण क्षेत्र में हमने ऐसे कुछ उद्योगों की पहचान की है जो समुचित प्रोत्साहन दिए जाने पर काफी रोजगार अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं: वस्त्रोद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पैट्रोलियम, रसायन और पैट्रो-रसायन, चमड़ा तथा ओटोमोबाइल। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन तथा साफ्टवेयर बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

वस्त्र

60. पिछले दो बजटों ने वस्त्र उद्योग, विशेषकर सूती वस्त्रोद्योग के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) योजना के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। इस निधि के लिए, मैं आगामी वर्ष आवंटन को 435 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 535 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्क रकीम (एस.आई.टी.पी.) अक्तूबर, 2005 में आरम्भ की गई थी जिसका उद्देश्य 25 वस्त्रोद्योग पार्क तैयार करना था। अभी तक, 7 पार्क रकीकृत किए जा सके हैं तथा 10 पार्कों के विकास हेतु पहचान कर ली गई है। इस योजना के लिए मैं 189 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

61. सरकार का 2006-07 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिससे इस सुनहरी रेशे की क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। एक राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। मैं एक सांकेतिक प्रावधान कर रहा हूं तथा यह आश्वासन देता हूं कि परिव्यय को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात अपेक्षित धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

हथकरघा

62. पिछले बजट में हथकरघा क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई थी जिनमें जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा हेतु योजनाएं भी शामिल हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वयित किया जा रहा है। इस बारे में समूहन विकास दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। 2006-07 में 50 करोड़ रुपये की लागत पर 100 अतिरिक्त समूहों को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। देश के विभिन्न भागों में यार्न डिपो स्थापित किए जाएंगे जिससे बुनकरों को यार्न की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। जिस प्रकार, "वूलमार्क" को एक पहचान मिल चुकी है, उसी प्रकार "हैंडलूम" मार्क को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। टीयूएफएस की तरह ही हथकरघा क्षेत्र के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिससे सावधिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा सके। मैं आगामी वर्ष के लिए हथकरघा क्षेत्र हेतु प्रावधान की राशि 195 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 241 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

63. इस बात को मानते हुए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से कृषि तथा रोजगार सृजन तथा उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बैंक ऋण के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाएगा। इस क्षेत्र, विशेषकर कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना तथा बाजार विकास के लिए पुनर्वित्त ऋण प्रदान करने हेतु नाबार्ड 1000 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ एक अलग सुविधा आरम्भ करेगा। सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी। तंजावुर रिथित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र को एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

पैट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रो-रसायन

64. पैट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रो-रसायन क्षेत्र में भारी निवेश तथा रोजगार की संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैट्रोलियम, रसायन तथा पैट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्य बल में वैश्विक स्तर के विकासकों तथा निवेशकों को शामिल किया जा रहा है। आशा है कि 2006-07 में ऐसे कम से कम तीन निवेश क्षेत्र विकसित कर लिए जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी

65. सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं (आई.टी.ई.एस.) के विस्तार के साथ अब यह सही समय है कि सेमी-कंडक्टर तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले आईटी उत्पादों, जिनमें वेफर, सेमी कंडक्टर एसेम्बली टेस्ट विनिर्माण, फ्लैट एलसीडी/ओएलईडी/प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले तथा स्टोरेज डिवाइज शामिल हैं, के निर्माण के लिए भारत को एक मनपसंद गन्तव्य स्थल बनाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही एक नीति की घोषणा की जाएगी। ऐसी सुविधा (विंडो) आरम्भ करने के लिए मैं अर्थ क्षमता अंतर निधिकरण तथा भारत अवसंरचना वित कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) के मौजूदा साधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे नए उद्यमों के लिए इक्विटी भागीदारी तथा/अथवा अर्थ क्षमता अंतर का निधिकरण प्रदान किया जा सके। निवेश की गति बढ़ाने के लिए यह सुविधा तीन वर्ष तक जारी रहेगी।

लघु और मझोले उद्यम

66. लघु और मझोले उद्यम (विकास) विधेयक के पेश किये जाने और 10 अगस्त, 2005 को घोषित ऋण नीति से, मेरा विश्वास है कि लघु और मझोले उद्यमियों की विचारधारा में परिवर्तन

हुआ है। आकार बढ़ाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में नया जोर दिया जा रहा है। शेयरधारकों के साथ उचित परामर्श और सलाहकार समिति की सिफारिश पर लघु उद्योग मंत्रालय ने अनारक्षण के लिये 180 मदों को चुना है।

67. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उधार देने की प्रक्रिया को नई गति देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

- सेवा क्षेत्रक में एस.एम.ई को मान्यता दी जाय और सेवा क्षेत्रक में लघु उद्यमियों को विनिर्माण क्षेत्रक के लघु उद्यमियों के समान माना जाय।
- मार्च, 2006 के अन्त में ऋण गारंटी निधि का कार्पस 1,132 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच वर्षों में 2,500 करोड़ रुपये किया जाय। मैं वर्ष 2006-07 में 118 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।
- सभी ऋणों के लिये एक कालिक गारंटी शुल्क 2.5 प्रतिशत से कम करके 1.5 प्रतिशत करने के लिये लघु उद्योग ऋण गारंटी न्यास (सी.जी.टी.एस.आई.) को सलाह दी जाय।
- सी.जी.टी.एस.आई. के अधीन चीफ प्रोमोटर्स के रूप में चुने गये लगभग 30,000 उधारकर्ताओं को बीमा संरक्षण प्रदान किया जाए। बीमित धनराशि प्रति लाभार्थी 200,000 रुपये होगी और किश्तों का भुगतान सी.जी.टी.एस.आई. द्वारा किया जाएगा।

68. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता परिषद (एम.एम.सी.सी.) ने एक पांच वर्षीय राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता कार्यक्रम को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है। आई.सी.टी. संवर्धन, मिनी टूल रूप्स, डिजाइन क्लीनिक्स और एस.एम.ई. के लिये विषयन सहायता की स्कीमों सहित दस स्कीमें तैयार की गई है। इनका कार्यान्वयन पीपीपी (सरकारी निजी भागीदारी) माडल में किया जाएगा और अगले वर्ष के दौरान वित्त पोषण को संबंधित किया जाएगा।

समूहन विकास

69. समूहन विकास माडल को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ही नहीं बल्कि औद्योगिक नगरों के नवीकरण और नये औद्योगिक नगरों के निर्माण के लिये भी लाभदायक रूप से अपनाया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले नौ क्षेत्रकों में एक या दूसरे रूप में अब इस माडल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन क्षेत्रकों में खादी और ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि उत्पाद और औषधीय पौधे शामिल हैं। समूहन विकास के पर्यवेक्षण और प्रगति की मानिटरिंग के लिये एक समूह को अधिकारिता प्रदान करना लाभदायक होगा। अतः प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने का निर्णय लिया है जो समूहन विकास की नीति निर्धारित करेगा और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा।

VIII सेवा क्षेत्रक

पर्यटन

70. वर्ष 2005 में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3.92 मिलियन हो गई थी। यह अभी भी भारत की क्षमता का एक हिस्सा मात्र है। वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन मंत्रालय:-

- 15 पर्यटक स्थानों और सर्किटों का विकास एक एकीकृत क्षेत्र विकास योजना अपना कर करेगा;

- विद्यमान पर्यटन स्थलों और सर्किटों के समीप हस्तशिल्प, हथकरघों एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण दक्षता वाले 50 गांवों का पता लगायेगा और पर्यटक अनुभव बढ़ाने के लिये उन्हें विकसित करेगा; और
- छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्यों में 4 नये होटल प्रबंधन संस्थानों की स्थापना करेगा।

मैं आयोजना आवंटन की राशि को 786 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 830 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

विदेशी व्यापार

71. चालू वर्ष में पाण्य निर्यातों में 18 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। आयात अधिक हैं, लेकिन इनका स्वागत है क्योंकि ये बढ़े हुए पूंजी निवेश एवं औद्योगिक कार्यकलाप के संकेत हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय ने हमारे निर्यातकों के लिए सहायक वातावरण तैयार करने के लिए मिलकर कार्य किया है तथा हम वर्ष 2008-09 तक विश्व निर्यातों में अपना हिस्सा दुगुना कर 1.5 प्रतिशत पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

IX आधारभूत ढांचा

दूरसंचार

72. भारत में दूरसंचार क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक तेज वृद्धि दरों वाले देशों में से एक है। जनवरी, 2006 के अंत में टेली-घनत्व 11.75 प्रति सेंकड़ा था। महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिसम्बर, 2007 तक 250 मिलियन कनेक्शन को प्राप्त करना है तथा मैं सफलता के प्रति आश्वस्त हूं। मैं वर्ष 2006-07 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से 1,500 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

73. तीन वर्षों में 50 मिलियन से ज्यादा ग्रामीण कनेक्शन दिए जाएंगे और इसके पश्चात कनेक्शन मांग पर उपलब्ध होंगे। ग्रामीण भारत तथा शहरी भारत के बीच डिजिटल अंतराल को पाट दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेलुलर टेलीफोनी के लिए आधारभूत ढांचा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संचार मंत्री भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन के लिए एक मिथेयक बजट सत्र में लाएंगे।

विद्युत

74. ईधन, मुख्यतया एल.एन.जी. तथा कोयले की कमी के कारण वर्ष 2005-06 में विद्युत उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज की गयी है। मांग-पूर्ति के बीच असंतुलन बना हुआ है। उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 82 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा एक से तीन वर्ष की अवधि में इनके पूरा हो जाने के पश्चात् इससे सरकारी क्षेत्र में 33,000 मेगावाट क्षमता तथा निजी क्षेत्र में 6,500 मेगावाट क्षमता की वृद्धि होगी। इसमें से लगभग 15,000 मेगावाट का उत्पादन 31 मार्च, 2007 तक चालू हो जाएगा।

75. विद्युत मंत्रालय ने प्रत्येक 4,000 मेगावाट की पांच अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की गयी हैं, जिसमें दो पिट-हेड (छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश में) तथा तीन स्टीय (गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में) होंगी। हमारा इरादा है कि 31 दिसम्बर, 2006 से पहले इन परियोजनाओं का काम शुरू हो जाय।

76. केवल क्षमता वृद्धि पर्याप्त नहीं है; हमें पारेषण तथा वितरण क्षेत्र में गहन एवं स्थायी सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्थकारी एवं अधिकार प्राप्त ढांचे के सृजन हेतु प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

77. पवन ऊर्जा सहित गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 3,075 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 31 दिसम्बर, 2005 तक इस लक्ष्य को पार कर लिया गया था तथा 3,650 मेगावाट क्षमता संस्थापित की गयी थी। मैं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अगले वर्ष में 597 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

78. सभी राज्यों ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। चालू वर्ष में 10,000 गांव विद्युतीकृत किए जायेंगे और 2006-07 में 40,000 और गांवों को विद्युतीकृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता की कुंजी वितरण, बिलिंग और संग्रहण हेतु फ्रेवाइजीज की नियुक्ति और समुचित वाणिज्यिक और संविदात्मक व्यवस्थाएं हैं।

कोयला

79. कोयला नीति की व्यापक समीक्षा की जा रही है। इस वर्ष विद्युत, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रकों तथा राज्य सरकारों की कैपिटिव खपत हेतु 45 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के लिए 2012 तक की अवधि हेतु ब्लाक आरक्षित करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत परियोजनाओं हेतु 20 बिलियन टन के कोयला भंडारों के ब्लाक समाप्त कर दिए जाएं। कैपिटिव खपत की परिभाषा भी संशोधित की जाएगी ताकि इस्पात, सीमेंट और विद्युत कंपनियों के साथ सुदृढ़ आपूर्ति संविदाओं वाले उत्पादकों द्वारा कोयले के खनन की अनुमति दी जा सके। सेंट्रल माइन्स प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की भण्डार की पुष्टि करने की ड्रिल क्षमता सिर्फ 200,000 मीटर प्रतिवर्ष है और इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

पैट्रोलियम

80. ऊर्जा संरक्षण सरकार की कार्यसूची में उच्च स्थान पर है। नई खोज लाईसैंसिंग नीति (एनईएलपी) के पांच दौरों में 110 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब एनईएलपी-VI के अंतर्गत अपनी सबसे बड़ी पेशकश की है। 55 ब्लाकों और 355,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की, जो पिछले राउंड से तीन गुणा बड़ी है, निवादायें दी जा चुकी हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संघटकों में निवेश के अतिरिक्त हम शोधन, पाइप लाईन और हरित ईंधन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अकेले शोधन क्षेत्रक में अगले कुछ वर्षों में 22,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

सड़क परिवहन

81. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) निरंतर प्रभावशाली प्रगति कर रहा है। कैलेंडर वर्ष 2005 में अब तक की सबसे अधिक संख्या व मूल्य की संविदाएं दी गई थीं। मैं एनएचडीपी के लिए बजटीय सहायता 9,320 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2006-07 में 9,945 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

82. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 4,618 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। मैं 2006-07 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 550 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

83. सरकार ने 1,000 किलोमीटर के पहुँच नियंत्रित एक्सप्रेस भार्गों के विकास का निर्णय भी लिया है। ये नई सीध पर होंगे और अभिकल्पना, निर्माण, वित्तपोषण और प्रचालन (डी बी एफ ओ) माडल पर बनाए जाएंगे। वडोदरा-मुंबई, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-आगरा, बंगलौर-चैन्नई, और कोलकाता-धनबाद खंडों की पहचान की गई है। ग्राहियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

84. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पुनर्संरचना की जाएगी और इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। इसे सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) की अनेक परियोजनाओं को संभालने की क्षमता वाला बहुविषयक निकाय बनाया जाएगा। योजना और गुणवत्ता आश्वासन, मानकीकरण, विवाचन, सड़क-सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास में नए कौशल क्षेत्र सृजित किए जाएंगे।

समुद्री विकास

85. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी.) का अनुमोदन कर दिया है। सिर्फ पत्तन क्षेत्र के लिए 55,804 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 101 परियोजनाओं का कार्य जारी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, नौवहन तथा पत्तन, जिसमें कांडला, जे.एन.पी.टी. तथा पारादीप में सरणियों को गहरा करने का कार्य शामिल है। मैं नौवहन विभाग के लिए योजना आवंटन की राशि में 37 प्रतिशत की वृद्धि कर 735 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

86. देश के पूर्वी भाग में एक गहरे ड्राफ्ट पत्तन की आवश्यकता है। मुझे यह धोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में एक नए गहरे ड्राफ्ट पत्तन के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है। विद्यमान राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, चैन्नई का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय समुद्री अकादमी के रूप में किया गया है तथा इसे संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर मुम्बई, कोलकाता तथा विशाखापत्तनम में स्थित होंगे।

87. भारत आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) का निगमन किया गया है तथा निधियों के लिए प्रथम प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधिपोषण हेतु अनेक परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। गुजरात में तीन सड़क परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है तथा 31 मार्च, 2007 के पूर्व इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

X वित्तीय क्षेत्रक

बैंकिंग, बीमा और पेंशन

88. 1993-94 में बैंकिंग क्षेत्रक में आरम्भ किए गए सुधारों के भाग के रूप में विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से बैंकों की पूंजी में वृद्धि की गयी थी। अभी तक, सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 16,809 करोड़ रुपये दिये हैं। पूर्व में निरंतर निर्गम प्रतिभूतियों का योग करमै पर कुल निवल पूंजी सहायता 22,808 करोड़ रुपये की है। पूंजी सहायता के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को

पूरा करने वाला एक सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्रक उभरकर सामने आया है। हम उस चरण में पहुँच गए हैं जब हम सरकार तथा बैंकों के बीच विशेष व्यवस्थाओं को समाप्त कर सकते हैं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् मैं लेन-देन नहीं की जा सकने वाले विशेष प्रतिभूतियों को लेन-देन योग्य, एस.एल.आर. भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपांतरण के माध्यम से विशेष प्रतिभूतियों को खोलने का प्रस्ताव करता हूँ। यह अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुयी ऋण आवश्यकताओं के आलोक में उत्पादक क्षेत्रकों को उधार के लिए बैंकों के अतिरिक्त संसाधनों की प्राप्ति को सुगम बनाएगा।

89. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि के.पी.नरसिम्हन समिति की नियुक्ति बीमा संबंधी व्यापक कानून की अनुशंसा के लिए की गयी थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है। वर्ष 2006-07 में बीमा संबंधी एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का मेरा इरादा है।

90. बैंकिंग नियमों में संशोधन करने तथा पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण विधेयक संसद के समक्ष हैं। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने इसकी अनुशंसा की है। मैं माननीय सदस्यों से सरकार से सहयोग करने तथा इन विधेयकों को पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

पूंजी बाजार

91. हाल के महीनों में पूंजी बाजार ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। विगत डेढ़ वर्ष में किए गए उपायों से यह बाजार सुव्यवस्थित, व्यापक और सुदृढ़ हुआ है। इस दिशा में और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है। अतः मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

- सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेश की सीमा 1.75 बिलियन डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन डालर तथा कारपोरेट ऋण में एफआईआई निवेश की सीमा 0.5 बिलियन डालर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन डालर करना;
- म्युचुअल फंडों द्वारा विदेशी लिखतों में कुल निवेश पर सीमा 1 बिलियन डालर से बढ़ाकर 2 बिलियन डालर करना और 10 प्रतिशत पारस्परिक शेयर धारिता की अपेक्षा को हटाना;
- सीमित संख्या में अर्हक भारतीय म्युचुअल फंडों को विदेशी एक्सचेंजों में कारोबार की जा रही निधियों में, संचयी रूप से 1 बिलियन डालर तक निवेश की अनुमति देना; और
- सेबी के तत्वाधान में सेबी द्वारा वसूले गए जुर्मानों और दंडों से निधिपोषित एक निवेशक संरक्षण निधि की स्थापना करना। इससे खुदरा निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा जिन्हें पूंजी बाजार का प्रमुख संचालक होना चाहिए।

इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी से विचार विमर्श किया गया है और वे यथासमय दिशा निर्देश जारी करेंगे।

92. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी परक्रान्त कारोबार प्रणाली में एनडीएस-ओ एम नामक अनाम इलेक्ट्रोनिक आर्डर मैचिंग ट्रेडिंग मोडयूल आरम्भ किया था। पहले चरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित निकायों, बैंकों और प्राथमिक डीलरों को इस प्रणाली में कारोबार करने की अनुमति दी गई थी। अब इस प्रणाली का विस्तार सभी बीमा कंपनियों के लिए किया गया है। बाजार

भागीदारों के उत्साहवर्धक रूख को देखते हुए और सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसकी पहुंच सक्षम स्युचुअल निधियों, भविष्य निधियों और पेंशन निधियों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

93. गत वर्ष अपने बजट भाषण में, मैंने कारपोरेट बांडों पर एक उच्चरत्तरीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अब हम कारपोरेट बांडों के लिए एकल, एकीकृत एक्सचेंज-ट्रेडेड मार्किट गठित करने के कदम उठाएंगे।

XI अन्य प्रस्ताव

अनुसंधान और विकास

94. हमारे उत्कृष्ट मानव संसाधनों में भारत को एक ज्ञान से परिपूर्ण समाज (नौलेज सौसाइटी) बनाने की क्षमता है। सरकार अनुसंधान और विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। कृषि विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना को शीघ्र ही बहुपक्षीय सहायता मिलने की आशा है और इसे जुलाई, 2006 में आरम्भ किया जाएगा।

95. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता बोर्ड ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से मूल निधिपोषण के साथ अनेक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना की है। सरकार इंक्यूबेटी उद्यमियों को समर्थकारी रियायतें प्रदान करेगी।

उत्कृष्टता के संरक्षण

96. गत वर्ष मैंने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर को उसे एक विश्वस्तरीय संस्था के रूप में विकसित करने में सहायता करने के लिए 100 करोड़ रुपये के एक अभूतपूर्व अनुदान से एक शुरुआत की थी। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि इस संस्थान ने आधुनिकीकरण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की मंजूरी प्राप्त की है और उसे कार्यान्वयित कर रहा है। इस वर्ष मुझे दूसरी ऐतिहासिक घटना को भी महत्व देना होगा। तीन बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने 150 वें वर्ष में प्रवेश किया है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय और भद्रास विश्वविद्यालय हैं। मैं प्रत्येक विश्वविद्यालय को विनिर्दिष्ट अनुसंधान विभाग या उस विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान से 150वें वर्ष के समारोहों की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष की समाप्ति पर मैं उनमें से प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये का दूसरा अनुदान देने का विचार रखता हूँ।

97. मैं एक उत्कृष्ट संस्थान से प्रतिष्ठित संस्थान बने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के लिए हरित क्रांति मैं इसके अग्रणी योगदान के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूँ।

98. कृषि यदि एक प्राचीन भारतीय कौशल है तो जैव प्रौद्योगिकी एक नया अग्रणी क्षेत्र है जिस पर भी भारत अग्रणी रहेगा। जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, केरल को एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया है।

कौशल विकास

99. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सरकार ने पांच वर्ष की अवधि में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। 100 आईटीआई को अब निजी क्षेत्रक की सहायता से इसके अंतर्गत लाया जा रहा है। शेष 400 आईटीआई को

करने के लिए बहुपक्षीय एजेन्सियों की सहायता मांगी गई है। मैं 2006-07 में इस प्रयोजन के लिए 97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। गत वर्ष घोषित कौशल विकास अभियान (एसडीआई) को एक सरकारी-निजी भागीदारी योजना के जरिए शुरू किया गया है और मैं इसके लिए 10 करोड़ रुपये के आरम्भिक प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि

100. एक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना होने पर, अब तक चालू वर्ष में पिछड़े के रूप में चिन्हित जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीआई) के अन्तर्गत 1,156 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया है। इस निधि को पंचायती राज मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा जा रहा है और मैं 2006-07 में 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

जम्मू और कश्मीर

101. सरकार जम्मू व कश्मीर को विशेष सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। 2006-07 के लिए राज्य-आयोजना 2,300 करोड़ रुपये नियत की गई है। इसके अतिरिक्त मैं बगलिहार परियोजना के लिए 230 करोड़ रुपये सहित जम्मू व कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के लिए 848 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्य को विद्युत क्षेत्रक में सुधार करने में समर्थ बनाने के लिए 1,300 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय आयोजना सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव करता हूं।

रक्षा व्यय

102. सरकार ने अधिकारी रैंक से नीचे (पी.बी.ओ.आर.) के सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कार्मिकों की बेहतर पेंशन संबंधी फायदों की लम्बे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा किया है। अधिकारी रैंक से नीचे लगभग 12 लाख सैन्य बल कार्मिकों को 1 जनवरी, 2006 से लगभग 460 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है और मुझे विश्वास है कि सदन इस निर्णय का स्वागत करेगा।

103. रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर बढ़ते हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए मैं रक्षा के लिए 2006-07 में आवंटन को 83,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं और इसमें पूंजी व्यय के लिए 37,458 करोड़ रुपये शामिल होंगे।

ई-गवर्नेंस

104. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का शीघ्र अनुमोदन किया जाएगा और 2006-07 में, मिशन भोड़ में 25 परियोजनाओं की शुरूआत की जाएगी। उनमें से एक परियोजना एमसीए-21 है जिससे कंपनियां अपनी विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कर सकें और सार्वजनिक सेवा केन्द्रों की स्थापना और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देने के लिए एक परियोजना शुरू की जा सके। सरकार का इचादा है कि अनेक सेवाओं को वेब-आधारित पद्धति में ऑन-लाइन लाया जाए जिनमें सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन पत्र, घरों, राशन कार्डों, अध्यापकों के स्थानान्तरण, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन पत्र, पुलिस में शिकायत दर्ज करना और जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना तथा भू अभिलेखों की प्रतियां शामिल हैं।

इतिहास एवं विरासत का सम्पादन

105. वर्ष 2007 में हम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम, जिसने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण किया, की 150वीं सालगिरह मनाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्यक्रम को उचित रूप में मनाया जाए, मैं इसकी तैयारी के क्रियाकलापों के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

106. गांधीजी से जुड़ी दो संस्थाएं, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, राजधानी और करतूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि, इंदौर को सहायता की आवश्यकता है। मेरा इन संस्थाओं के कार्पस में प्रत्येक के लिए वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ रुपये प्रदान करने का इरादा है।

107. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि फुटर्टीमर्ट्टी, वैदिक मन्त्रोचारण और रामलीला को यूनेस्को द्वारा "मानवता की मौखिक एवं अमृती विविधता" घोषित किया गया है। इन प्राचीन कलात्मक धरोहरों और मौखिक परम्पराओं को सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार किए जाने तक, मैं 2006-07 में 5 करोड़ रुपये का आरम्भिक प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

XII राजकोषीय समेकन

बारहवां वित्त आयोग

108. बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों को कार्यान्वयन किया जा रहा है। संचयी रूप से 1,03,710 करोड़ रुपये की राशि के राज्य ऋणों जा अब तक समेकन किया गया है। कर अन्तरण की नई योजना के तहत 2004-05 में 78,595 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष में राज्यों के हिस्से के रूप में 94,402 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। जहां तक सहायता अनुदानों का संबंध है, 2004-05 और 2005-06 (सं.अ.) में प्रदत्त राशियां क्रमशः 12,081 करोड़ रुपये और 25,134 करोड़ रुपये हैं। 2006-07 में कर-अंतरण और अनुदान दोनों काफी अधिक होंगे। जैसाकि आप बजट दरतावेजों में देख सकते हैं, राज्यों को इतने अधिक वित्तीय साधन कभी उपलब्ध नहीं कराए गये।

109. मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने ऋण समेकन और राहत के लिए बजट में उपयुक्त प्रावधान किया है। मैंने 2006-07 में वैट से होने वाले नुकसानों गदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है।

सब्सिडी

110. सब्सिडियों का मुद्दा एक विभाजक मुद्दा साबित होने जा रहा है, परन्तु मैं भाननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह अत्यावश्यक है कि यदि हम सब्सिडियों को गरीबों और वास्तव में जलस्तमंद लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में गम्भीर हैं तो हम इस मोर्चे पर प्रगति करें। मेरे मंत्रालय ने तीन प्रमुख सब्सिडियों-खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम के संबंध में संबंधित पक्षों से विस्तारपूर्वक विचार विर्मार्श किया है। हमने आम जनता के विचार भी मांगे हैं। उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों के प्रश्न पर वर्किंग ग्रुपों/समितियों ने विचार-मंथन किया है जिनमें अद्यतन डा. सी. रंगराजन समिति है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सब्सिडी के मुद्दे पर सर्वसम्पत्ति तैयार करने में सरकार की सहायता करें।

सकल बजटीय सहायता और सकल राजकोषीय धाटा

111. अध्यक्ष महोदय, मैं राजकोषीय क्षेत्र में दो ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, बाजिब दरों के जरिए बढ़े हुए राजरव संग्रहण, कर अनुपालन और कर आधार का विस्तार करने की रणनीति के मूर्त परिणाम सामने आ रहे हैं। केन्द्र के मामले में, सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से 2004-05 में 9.8 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, 2005-06 (संशोधित अनुपात) में और वह कर 10.5 प्रतिशत हो गया। सरकार का अनुमान है कि बेहतर कर प्रशासन के जरिए, यह 2006-07 (व.अ.) में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो जाएगा।

112. दूसरा, 2004-05, जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं; एक परिवर्तनकारी वर्ष सिद्ध हुआ है। 20 वर्षों के बाद सकल राजकोषीय घाटा उस वर्ष में आयोजना के लिए सकल राजकोषीय सहायता से कम रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि सरकार पूरी तरह उधार के जरिए योजना को वित्तपोषित नहीं कर रही है। क्या 2005-06 में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, इसका पता वास्तविक आंकड़ों के उपलब्ध होने के बाद ही त्रै सकेगा। तथापि, 2006-07 के बजट अनुमान में, मैं सकल राजकोषीय घाटे को योजना के लिए सकल बजटीय सहायता से बहुत कम की संख्या पर सीमित करने में सफल रहा हूं।

113. गत वर्ष, अनिच्छापूर्वक मुझे राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को विराम देना पड़ा था। मैंने 2005-06 के लिए राजस्व घाटा 2.7 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मैं गतत सिद्ध हुआ हूं। हमने दोनों क्षेत्रों में सुधार किया है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के किए राजस्व घाटा केवल 2.6 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा केवल 4.1 प्रतिशत होगा।

XIII वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान

114. मैं अब अगले राजकोषीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की ओर रुख करता हूं।

आयोजना व्यय

115. वर्ष 2006-07 के लिए आयोजना व्यय 172,728 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पूर्व वर्ष की तुलना में 20.4 प्रतिशत अधिक है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में; आयोजना व्यय 2004-05 में 26.6 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 (सं.अ.) में 28.3 प्रतिशत और 2006-07 (ब.अ.) में और बढ़कर 30.6 प्रतिशत हो गया है। यह सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार को इंगित करता है।

आयोजना-भिन्न व्यय

116. वर्ष 2006-07 में आयोजना-भिन्न व्यय 391,263 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2005-06 (ब.अ.) में आयोजना-भिन्न व्यय की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि सामान्य वृद्धि के कारण है और हाल के वर्षों में सबसे कम वृद्धियों में से है।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

117. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 563,991 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मैं केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 403,465 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 488,192 करोड़ रुपये होने का अनुमान करता हूं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा 84,727 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जी.डी.पी. का 2.1 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 148,686 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जी.डी.पी. का 3.8 प्रतिशत है। मुझे विश्वास है कि राजकोषीय सुधार प्रक्रिया 2006-07 में पुनः शुरू करने की अपनी वचनबद्धता को मैंने पूरा किया है।

भाग - ख

XIV कर प्रस्ताव

118. अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यू.पी.ए. सरकार के पहले बजट में और इससे अधिक दूसरे बजट में मैंने महत्वपूर्ण कर सुधारों का प्रयत्न किया था। इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। वर्ष 2004-05 में सकल कर राजस्व (अनन्तिम वार्तविक) पिछले वर्ष के वार्तविक कर राजस्वों की तुलना में 19.9 प्रतिशत बढ़े हैं और संशोधित अनुमानों के अनुसार 2005-06 में पिछले वर्ष के अनन्तिम वार्तविक की तुलना में उनके 21.4 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। यह आंकड़े हमारे इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि हमें अपनी कर दरें सामान्य और स्थिर रखनी चाहिए।

अप्रत्यक्ष कर

119. मैं अप्रत्यक्ष करों से अपने प्रस्ताव शुरू करूंगा। सबसे पहले सीमा शुल्क है।

120. सीमा शुल्क कम करने की सरकार की नीति के अनुसार मैं गैर-कृषि उत्पादों के लिये अधिकतम दर 15 प्रतिशत से कम करके 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा विश्वास है कि हम पूर्वी एशियाई दरों से काफी कम दूरी पर हैं।

121. अधिकतम दरों को कम करने पर कच्चे मालों और मध्यवर्ती वस्तुओं पर शुल्क कम करने की आवश्यकता है।

122. प्राथमिक इस्पात पर शुल्क 5 प्रतिशत है। मैं मिश्र इस्पात तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक अलौह-धातुओं पर शुल्क 10 प्रतिशत से कम कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह शुल्क दर लौह मिश्र धातुओं के लिये भी होगी।

123. वर्ष 2004-05 में, इस्पात की उच्च अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए मैंने स्टील मेल्टिंग स्कैप पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया था। इस्पात की कीमतों में गिरावट के आसे से मैं शुल्क को 5 प्रतिशत पर पुनर्बहाल कर इसे मूल इस्पात के समकक्ष लाने का प्रस्ताव करता हूं।

124. खनिज उत्पादों पर इस समय शुल्क 15 प्रतिशत है। मैं कुछ अपवादों के साथ इसे 5 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव करता हूं।

125. मैं कच्चे लोहे और सान्द्रों पर भी शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

126. रेफेक्टरीज में 10 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। रेफेक्टरीज के विनिर्माण हेतु अपेक्षित कई सामग्रियों में भी 10 प्रतिशत या उससे अधिक की दरों पर शुल्क लगाया जाता है। मैं इन शुल्कों को घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

127. बुनियादी अकार्बनिक रसायन महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियां हैं। मैं शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मूल साइकिल तथा असाइकिल हाइब्रॉकार्बन और उनके व्युत्पन्नों पर मैं शुल्क की दरें घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उत्प्रेरकों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

128. प्लास्टिक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। इसलिए मैं पीवीसी, एलडीपीई और पीपी जैसे प्लास्टिकों के बड़े भाग पर 10 प्रतिशत के शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, प्लास्टिक के लिए नाष्ठा के उपयोग पर शुल्क को घटाकर शून्य पर लाया जाएगा।

129. मैं रस्टाइरीन, ईडीसी तथा बीसीएम पर, जो प्लास्टिक हेतु कच्ची सामग्रियां हैं, शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

130. मैं महत्वपूर्ण औषधियों पर कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं 10 एड्स रोधी और 14 कैंसर रोधी औषधियों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कंतिपय जीवन रक्षक औषधियों, किट्स और उपस्करों पर शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। ये औषधियां सीमा शुल्क तथा प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) से भी छूट प्राप्त होंगी।

131. पैकेजिंग मशीनें खाद्य प्रसंस्करण सहित कई किस्म के उद्योगों में सहायक हैं। मैं पैकेजिंग मशीनों पर शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

132. मैं प्राकृतिक गैस, कच्चे पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन से संबद्ध पाइपलाइन परियोजना के संबंध में 10 प्रतिशत की रियायती परियोजना दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

133. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष मैंने राज्य स्तर के करों की प्रतिपूर्ति हेतु सभी आयातों पर सी.वी.डी. लगाने का प्रस्ताव किया था। यह लेवी-आईटी सॉफ्टवेयर को छोड़कर आईटीए आवद्ध मदों और उनकी निविष्टियों के आयातों पर ही लागू थी। अधिकांश राज्यों में वैट के लागू होने के बाद, मुझे व्यापार और उद्योग जगत से प्रतिवेदन मिले थे कि इस लेवी को सभी प्रकार के आयातों पर लगाया जाए। यह तर्क आश्वस्तकारी है और मैं कुछ अपवादों के साथ सभी आयातों पर 4 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस शुल्क के पूरे लाभ की अनुभाति सीमाशुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माताओं को प्रदान की जाएगी।

134. घरेलू वनस्पति उद्योग के संरक्षण हेतु मैं वनस्पति पर 80 प्रतिशत तक सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, जो दर कच्चे पॉम ऑयल पर लागू है।

135. निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) को अपनी वस्तुएं घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में रियायती दर पर निकासी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आयात शुल्कों के घटने से डीटीए इकाइयों तथा ईओयू के सीमाशुल्क अथवा सीवीडी के सम्बन्ध में एक समान दर होनी चाहिए। इसलिए मैं ईओयू द्वारा डीटीए के सम्बन्ध में निकासी से सम्बद्ध शुल्क दरों को सदृश वस्तुओं पर बुनियादी सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क के 25 प्रतिशत पर समायोजित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके बावजूद यह ईओयू को टैरिफ लाभ प्रदान करेगा अथवा कम से कम यह डीटीए इकाई के सम्मूल्य पर होगा।

136. अन्त में, मैं एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उत्पाद तथा सीमा शुल्क दोनों से संबद्ध है। सूती कपड़ा उद्योग दो वर्ष पहले प्रदान की गयी राहत से काफी लाभान्वित हुआ। मानव निर्मित कपड़ा उद्योग विकास और रोजगार का बाहक है। इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी मानव निर्मित फाइबर यार्न तथा फिलमेंट यार्न पर सीमाशुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही मैं सभी मानव निर्मित फाइबर तथा यार्न पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप, डीएमटी, पीटीए तथा एमईजी जैसी कच्ची सामग्रियों पर भी आयात शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। पैराक्रिसलीन पर आयात शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

137. मेरे पास सीमा शुल्क के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमारी मंशा सेनेट दर पर भी दरों को कवरेज करने की है जो इस समय 16 प्रतिशत है। केवल वातित पेय तथा कार ऐसी दो मदे हैं जिन पर अभी भी 24 प्रतिशत की उच्च दर लगायी जाती है। मैं इसमें पर्याप्त रूप से सुधार करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वातित पेयों पर सीमा शुल्क को घटाकर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कारों के सम्बन्ध में केवल छोटी कारों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क को घटाकर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रयोजनार्थ एक छोटी कार का तात्पर्य ऐसी कार से होगा जिसकी लम्बाई 4,000 एमएम से ज्यादा न हो और डीजल कार के सम्बन्ध में इंजन की क्षमता 1,500 सीसी से ज्यादा न हो तथा पेट्रोल कारों के सम्बन्ध में यह 1,200 सीसी से ज्यादा न हो। मुझे विश्वास है कि उद्योग जगत इस अवसर का उपयोग भारत को छोटी तथा ईंधन-किफायती कारों के विनिर्माण हेतु एक केन्द्र बनाने के बतौर करेगा।

138. मैं काउंटर में विक्रय होने वाले पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इंटरनेट से डाउन लोड होने वाले कंस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर पैकेजों को इस लेवी से छूट मिलेगी।

139. मैं डीवीडी ड्राइव्स, फ्लैस ड्राइव्स तथा कोम्बो ड्राइव्स को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

140. पैकेट बंद मदों सहित कई खाद्य मदों में शून्य उत्पाद शुल्क लगता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं संघनित दूध, आइसक्रीम, मांस तैयार करना, मछली और कुकुट, पैकिट्स पास्ता तथा खमीर को पूर्णतः उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। पैकेट बंद तैयार खाद्य वस्तुओं और शीघ्र तैयार होने वाले खाद्य मिश्रणों जैसे डोसा और इडली मिश्रणों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

141. चूंकि चर्म तथा जूते महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं, इसलिए मैं क्यूब्राकों तथा चेस्टनट नामक दो सब्जी रंगाई आसवनों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। 250 रुपये तक के थोक बिक्री मूल्य वाले जूतों पर पहले ही कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता। मैं 250 रुपये और 750 रुपये के बीच के खुदरा बिक्री मूल्य वाले जूतों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

142. वर्तमान में 2000 रुपये तक की कीमत वाले एलपीजी स्टोव पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं इस रियायती दर को मूल्य सीमा का ध्यान रखे बिना सभी एलपीजी स्टोवों पर प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

143. ऊर्जा किफायती लैम्पों में उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु, मैं कम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

144. मैं टेबल वेयर तथा किचनवेयर की विभिन्न किस्मों के बीच मौजूदा दर भिन्नताओं को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ। परिणामरवरूप, सिरेमिकवेयर तथा प्लास्टिकवेयर के समान ग्लासवेयर में उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत लगाया जाएगा।

145. कागज का शिक्षा में तथा पैकेजिंग में व्यापक उपयोग होता है। मैं विनिर्दिष्ट मुद्रण, लेखन तथा पैकिंग कागज पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

146. घरेलू तौर पर उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर तेल उद्योग विकास अधिनियम के अन्तर्गत उपकर लगाया जाता है। वर्ष 2002 में यह दर 1,800 रुपये प्रति मी. टन निर्धारित की गयी थी। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से परामर्श करने के बाद मैं इस उपकर को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आश्वस्त किया गया है कि यह वृद्धि तेल कंपनियों द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और इसका पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

147. मुझे व्यापार तथा उद्योग जगत से दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैंने कम्प्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कम्प्यूटरों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। उस उद्देश्य की काफी हद तक पूर्ति हो गयी है। घरेलू विनिर्माताओं ने 12 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को फिर से लगाने की मांग की है ताकि वे सेनेट क्रेडिट लेने में तथा आयातों से होने वाली प्रतिस्पर्द्ध का मुकाबला करने में सक्षम हो सकें। मैं इस अनुरोध को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं। चूंकि 12 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र होगा, इसलिए कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

148. दूसरा अनुरोध सेट टॉप बॉक्सेज पर उत्पाद शुल्क लगाने से सम्बद्ध है। मैं इस अनुरोध को स्वीकार करने और 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर शून्य पर करने का भी प्रस्ताव हूं। यह परिवर्तन विभिन्न प्रकार के सेट टॉप बॉक्स पर शुल्क दरों को बराबर कर देगा।

149. यदि मैं सिगरेट पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाता हूं तो समग्र तौर पर मैं अपने को कर्तव्य पालन में असफल पाऊंगा, इसलिए मैं सिगरेट पर उत्पाद-शुल्क में लगभग 5 प्रतिशत बढ़ातरी करने का प्रस्ताव करता हूं।

150. उत्पाद तथा सीमा टैरिफों से सम्बद्ध कठिनाई इनको प्राप्त अनेक छूटों की वजह से है। व्यापक समीक्षा के आधार पर, मैं उन कई छूटों को हटाने का प्रस्ताव करता हूं जो अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रदान की गयी हैं। व्यापक रूप में, ऐसी छूटें जो उपयोगकर्ता-आधारित हैं, अथवा जिन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी है अथवा जिनके सम्बन्ध में प्रमाणन की आवश्यकता है अथवा जो विवादों का कारण बनती है, उन्हें केवल कुछ अपवादों के साथ रद्द किया जा रहा है। तथापि, एसएसआई क्षेत्र हेतु छूट यथावत बनी रहेगी।

151. हमने कुछ और अधिसूचनाओं की पहचान की है और जिन्हें हटाने की आवश्यकता है। तथापि, अन्तिम निर्णय लेने से पहले मैं मंत्रालय के वैबसाइट पर ऐसी अधिसूचनाओं की सूची डालने और टिप्पणियां आमंत्रित करने का प्रस्ताव करता हूं।

152. अब मैं सेवा कर का उल्लेख करता हूं। वर्ष 2005-06 में सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी का 5:1 प्रतिशत अनुमानित है। स्वाभाविक रूप से इसका राजकोष में भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में निरन्तर दिशा का पालन करते हुए मैं सेवा कर नेट के अन्तर्गत और सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। नई सेवाएं जिन्हें शामिल किया जाना है, उनमें एटीएम आपरेशन, रख रखाव तथा प्रबन्धन, रजिस्ट्रार, शेयर अन्तरण एजेन्ट तथा किसी निर्गम के बैंकर, विज्ञापन ख्याल अथवा समय की विक्री, प्रिंट मीडिया को छोड़कर, कम्पनियों के खेलकूद इवैन्ट्स को छोड़कर अन्य इवैन्ट्स का प्रायोजन, किफायती श्रेणी के यात्रियों को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा; रेल माल भाड़ा प्रभारों को छोड़कर रेल के सम्बन्ध में कंटेनर सेवा व्यवसाय सहायता सेवाएं; नीलामी कार्य, वसूली एजेंट, पोत प्रबन्धन सेवा; क्रूसपोतों पर यात्रा; और लोक सम्पर्क प्रबन्ध सेवाएं शामिल हैं।

153. मैं अब सेवा कर के अधीन करिपय सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उनका ब्यौरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वह बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

154. पट्टा और किराया खरीद उद्योग को ब्याज सहित भुगतानों के सभी संघटकों पर सेवा कर लगाने की वजह से कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मैं इस विसंगति में सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार सेवा के मूल्य परिकलन में मूल धन के ब्याज तथा किश्तों को कम कर दिया जाएगा।

155. मेरे विचार में इस बात पर आम सहमति है कि देश को राष्ट्रीय स्तर की वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की ओर उन्मुख होना चाहिए और जिसकी भागीदारी केन्द्र और राज्यों के मध्य होनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि हम 1 अप्रैल, 2010 को जीएसटी को लागू करने की तारीख के रूप में मानें। पूरे विश्व में मालों और सेवाओं पर कर की एक ही दर लगाई जाती है, जो जी.एस.टी. का आधार है। लोगों को जी.एस.टी. के विचार का अभ्यर्त होना चाहिए। अतः हमें उत्तरोत्तर सेवा कर दर और सेनेवेट दर की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसलिए मैं इस वर्ष एक कदम आगे बढ़कर सेवा-कर-दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे यह कहना है कि चूंकि भुगतान किया गया सेवा कर देय सेवा कर अथवा देय उत्पाद शुल्क के लिए क्रेडिट किया जा सकता है, इसलिए निवल प्रभाव बहुत कम होगा।

प्रत्यक्ष कर

156. मैं अब अपने प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं।

157. अच्छी खबर यह है कि वैयक्तिक आय कर अथवा कंपनी आय कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

158. दूसरी खुशखबरी यह है कि कोई नए कर नहीं लगाए जा रहे हैं।

159. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छ. में एक योजना में करिपय श्रेणी के व्यक्तियों के लिए विवरणी दायर करने की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी।

160. मैं साम्यता की दृष्टि से करिपय कर दरों को मामूली तौर पर संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। जहां कंपनी कर दर 30 प्रतिशत हैं, वहीं न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के अन्तर्गत दर, खाता लाभों का केवल 7.5 प्रतिशत है। मैं इस दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं, जो अभी भी सामान्य दर का एक तिहाई है। मैं खाता लाभों के परिकलन में प्रतिभूतियों से अंजित दीर्घावधि पूँजी लाभों को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने पहले ही मैट अदा करने वाली कम्पनियों को आगामी पांच वर्षों के दौरान मैट के लिए उधार लेने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी है। मैं इस अवधि को सात वर्षों तक बढ़ाने तथा ब्याज देयता के परिकलन के समय मैट उधार के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं।

161. प्रतिभूतियों के लेन-देन कर (एस.टी.टी.) सम्बन्धी दरें उस समय निर्धारित की गयी थीं जब कि प्रतिभूतियों कीमतें काफी कम थीं। प्रतिभूतियों के लेन-देनों में स्पष्ट पूँजी लाभों में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए मैं एसटीटी की सभी दरों के संबंध में सभी स्तरों पर 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूं।

162. आयकर अधिनियम की धारा 80जक ढांचागत सुविधाओं के संबंध में लागू होती है। किसी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए समाप्त तारीख 31 मार्च, 2006 है। मैं इस अवधि को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत क्षेत्र के संबंध में अति विशाल परियोजनाओं को देखते हुए मैं इस तारीख को 31मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

163. पिछले वर्ष, मैंने बचतों के संबंध में प्रावधान तैयार किए थे। उनमें मियादी जमा राशियों को शामिल नहीं किया गया था। यह मांग थी कि कतिपय अवधि वाली मियादी जमा राशियों को कर छूट हेतु पात्र माना जाए। मैं आय कर अधिनियम की धारा 80ग में किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम पांच वर्ष की अवधि वाली मियादी जमा राशियों के निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं धारा 80गगग में कतिपय पेंशन निधियों के संबंध में अंशदान के सन्दर्भ में 10,000 रुपये की सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव करता हूं जिसकी, अधिकतम सीमा 100,000 रुपये होगी।

164. मैं आयकर अधिनियम में असीमित विस्तार वाली म्यूचुअल फंड की इक्विटी संबंधी योजनाओं की परिभाषा को सेवी द्वारा अपनाई गई परिभाषा के समरूप बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं लाभांश वितरण कर से छूट के प्रयोजन से असीमित विस्तार वाली इक्विटी योजनाओं तथा सीमित अवधि वाली इक्विटी योजनाओं को भी एक समान माने जाने का प्रस्ताव करता हूं।

165. मैंने आय कर अधिनियम में दी गई छूटों पर फिर से विचार किया है। इसके परिणामस्वरूप, मैं धारा 10(23छ) के अंतर्गत छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं क्योंकि व्याज दरें इतनी कम होने के कारण अब यह छूट प्रासंगिक नहीं है।

166. अन्य बैंकों की तरह सहकारी बैंक भी ऋणदाता संरक्षण एं हैं और उन्हें अपने लाभ पर, कर अदा करना चाहिए। बुनियादी कृषि ऋण समितियां तथा बुनियादी सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अभी तक विशेष स्थिति में हैं और इसलिए वे आगे कर अधिनियम की धारा 80(त) के अंतर्गत कर से मुक्त रहेंगे। तथापि, मैं अन्य सभी सहकारी बैंकों को इस धारा के दायरे से बाहर करता हूं।

167. धारा 54उग तथा धारा 54उघ कर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मैं धारा 54उग के दायरे को केवल दो संरक्षणाओं अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा आरईसी तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं। नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी जो कि बैंक हैं, के लिए हमने व्यय लागत वाली निधियां जुटाने हेतु जीरो कूपन बांडों का मार्ग खोल दिया है। आवश्यकता होने पर सरकार इन संरक्षणाओं को उपयुक्त समर्थन प्रदान करेगी जिससे वे अपने अधिदेशों को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु संसाधन प्राप्त कर सकें। मैं धारा 54उ घ के लाभ को भी 1 अप्रैल, 2006 से वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूं जो कि अब वास्तव में अनावश्यक बन चुका है।

168. वित्त संबंधी स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त की है कि चैरीटेबल संरक्षण आय कर अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग करती हैं। मैं ऐसे एक दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो कि अनाम अथवा नकली दान राशियां प्राप्त करने से संबंधित हैं। तदनुसार, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्णतया चैरीटेबल संरक्षणाओं को मिलने वाली अनाम अथवा नकली दान राशि अथवा किसी संरक्षण को दिए जाने वाले दान पर उच्चतम सीमात दर पर कर लगाया जाएगा। आंशिक धार्मिक और आंशिक चैरीटेबल संरक्षणाओं/न्यासों को ऐसे दानों पर तभी कर लगाया जाएगा यदि दान विशिष्ट रूप से शैक्षिक अथवा चिकित्सा प्रयोजन के लिए है। तथापि, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूर्णतया धार्मिक संरक्षणाओं और धार्मिक न्यासों को ऐसे दान नए प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

169. राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों ने शिकायत की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र भूतों पर संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भूतों से अलग प्रकार का कर लगाया जाता है। मैं इस असंगति को दूर करके इन्हें समान मानने का प्रस्ताव करता हूं।

170. आय कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) आय तथा व्यय के अभिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। उच्च मूल्य वाली लेनदेन संबंधी वार्षिक सूचना विवरणियों की छानबीन से पता चलता है कि 60 प्रतिशत लेनदेनों में पैन का उल्लेख नहीं किया जाता। इसलिए, मैं कतिपय मामलों में पैन जारी करने के अधिकार को स्व-विवेक पर लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कतिपय मामलों में पैन के लिए आवेदन करने हेतु लोगों को निर्देश देने का अधिकार लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं समय आने पर और अधिक लेन-देनों को अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिनके लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मैं वार्षिक सूचना विवरणी में रिपोर्ट किये जाने हेतु कुछ और लेनदेनों को अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

171. पिछले वर्ष, मैंने दो नए करों की शुरूआत की थी। बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) एक वरदान की तरह सावित हुआ है; साधारण राजस्व के लिए नहीं क्योंकि यह तो इसका उद्देश्य था ही नहीं बल्कि उन उल्लेखनीय रास्तों के लिए जो इसने बना दिए हैं। उदाहरण के लिए, घांटनी चौक की एक बैंक शाखा में बीसीटीटी के माध्यम से भारी नकदी निकासी का पता चलने से आयकर विभाग को ऐसी तीन कंपनियों तक पहुंचने में सफलता मिली जो व्यापारियों से कटौती पर डिमांड ड्राफ्ट खरीदने का कारोबार कर रही थी तथा बिक्री कर तथा आय कर दोनों से बचने में इन व्यापारियों की सहायता कर रही थी। ये कंपनियां डिमांड ड्राफ्ट अपने स्वयं के खाते में जमा कर लेती थीं और नकदी निकालती थीं। 18 महीनों की अवधि में उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए के काले धन को वैध धन में बदल दिया। बीसीटीटी ने जाली बिलों, आवास प्रविष्टियों, कृत्रिम हानि के दावे और फर्जी फर्मों का पता लगाने में भी विभाग की मदद की है। मैं बीसीटीटी को कुछ और समय तक जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं जब तक एआईआर प्रणाली सभी महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन पकड़ने में सक्षम न हो जाए।

172. अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) की शुरूआत एक राजस्व जुटाने वाले उपाय के रूप में की गई थी। एफबीटी को समस्तरीय इक्विटी तथा विषमस्तरीय इक्विटी और समान्तर के सिद्धांतों पर न्यायोचित माना जा सकता है। फिर भी, मैंने खुले मन से इसकी पुनरीक्षा की है। मैंने शीर्ष वाणिज्य मंडलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी ध्यान दिया है। मैं आयकर अधिनियम के अध्याय XII-J में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं:

- 'पर्यटन और यात्रा' के रूप में लाभ के मूल्य को 20 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत पर माना जाय;
- एयरलाइन कंपनियों और नौवहन उद्योग के भामले में 'आतिथ्य' और 'होटल' के खाने व रहने की सुविधाओं का प्रयोग' के रूप में लाभ के मूल्य को 20 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत पर माना जाय;
- डाक्टरों को वितरित दवाइयों व चिकित्सा उपस्करों के मुफ्त नमूनों पर खर्च को छोड़ना शामिल न किया जाय;
- ब्रांड अंबेसेडर और सेलीब्रेटी इन्डोर्समेंट पर हुए खर्च को शामिल न किया जाय; और
- धारा 115 बख(1) (ग) के अंतर्गत 100,000 रुपये की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना ताकि किसी नियोक्ता द्वारा प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 100,000 रुपये से अधिक अनुमोदित सेवा निवृत्ति निधि में अंशदान पर एफबीटी लागू हो सके। धारा 80ग के अंतर्गत किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में 100,000 रुपये तक के अंशदान पर पहले ही छूट है। माननीय सदस्य देखेंगे कि इन दो उपबंधों के तहत कर्मचारी के हित के लिए अब 200,000 रुपये प्रतिवर्ष तक कर-मुक्त अंशदान हो सकता है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों के भारी संख्या के मामले में यह छूट

इन परिवर्तनों के साथ ही मुझे विश्वास है कि एफबीटी पर बहस को विराम मिलेगा। मैं एक बार फिर सभी संबंधित को रमरण कराना चाहूँगा कि समता के सिद्धांत पर एफबीटी न्यायोचित है।

कर-प्रशासन का आधुनिकीकरण

173. मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कर प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। आयकर और सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग व्यवसाय प्रक्रिया रीइंजीनियरिंग (बी.पी.आर.) शुरू करेंगे। राष्ट्र व्यापी नेटवर्क, राष्ट्रीय डाटाबेस सृजित करते हुए 510 शहरों में 745 आयकर कार्यालयों और 245 शहरों में 550 सीमाशुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों को जोड़ेगा। राष्ट्रीय डाटा केंद्र, डाटा भांडागारण सुविधाओं और आपदा राहत स्थलों की स्थापना की जा रही है। विवरणियों का क्षेत्राधिकार-मुक्त प्ररत्तीकरण, खातों की स्थिति का आनलाईन पता लगाना और आयकर की वापसी अदायगियां संभव होंगी। सीमा शुल्क विभाग में जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) शुरू करने से माल को रखने के समय में कमी आएगी। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का ई-भुगतान संभव होगा। दोनों विभाग 2006 के अन्त तक पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क वाले हो जाएंगे।

174. हमारी सरकार के दो बजटों ने कई नवीनतायें देखी हैं तिंग आधारित बजट, आउटकम बजट आदि। आज, मैं सदन के समक्ष एक और नई बात रखता हूँ: छोड़े गए राजस्व संबंधी विवरण-विश्वभर में कर व्यय विवरण के रूप में जाना जाता है। यह विवरण सामान्य कर व्यवस्था से विचलनों पर रोक लगाएगा। यह प्रयोग पहला प्रयास है जो आने वाले वर्षों में बिल्कुल ठीक कार्य करेगा।

वैट और केन्द्रीय बिक्री कर

175. इस सदन को विदित है कि अधिकतर राज्यों ने 1 अप्रैल, 2005 से वैट लागू कर दिया है और सर्व सम्मत राय है कि वैट बहुत सफल रहा है। मुझे आशा है कि वैट-भिन्न राज्य शीघ्र मुख्य धारा में शामिल होंगे क्योंकि सुधारों का अगला चरण सभी राज्यों के वैट लागू करने पर निर्भर करेगा। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और केन्द्र से अनुरोध किया है कि राजस्व की संभावित हानि के लिए उनकी क्षतिपूर्ति की जाय। सरकार ने प्रस्ताव किया है कि राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति मौद्रिक और गैस-मौद्रिक उपायों के माध्यम से की जा सकती है जो साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यों के राजस्व उत्प्लावक बने रहें। एक बार अधिकार प्राप्त समिति और सरकार एक समझौते पर पहुँच जाएं तब मैं विधायी परिवर्तनों और पूरक मांग सहित दृढ़ प्रस्तावों के साथ सदन में वापस आऊंगा।

176. इस समय सीएसटी और वैट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण हो गया है कि घरेलू प्रयोग के लिए द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) के मूल्य संतुलित किए जाएं। राज्य एलपीजी (घरेलू) पर उच्च दरों पर कर लगा रहे हैं। उन्हें भी पैट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे मूल्य भार के एक हिस्से को वहन करना चाहिए। इसलिए एलपीजी (घरेलू) के मूल्य को संतुलित करने के लिए मैं सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी (घरेलू) को 'धोषित वस्तुओं' की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

177. प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे कर प्रस्तावों से लाभग 4,000 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होना अनुमानित है। अप्रत्यक्ष करों की ओर लाभ का अनुमान 2,000 करोड़ रुपये है।

XV निष्कर्ष

178. अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि विश्व ने भारत की क्षमता को पहचान लिया है। अब यह हम पर निर्भर है कि जिस पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का विशेष अधिकार दिया गया है वह इस देश की महानता और इसके लोगों की क्षमता की पुनः खोज करे। भारत के युवक किले बना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हवाई किले हैं, परन्तु जैसा कि हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, "यदि आपने हवाई किले बनाए हैं, तो आपका कार्य व्यर्थ नहीं होगा। यह वहीं होंगे जहां उन्हें होना चाहिए। अब उनके नीचे बुनियाद रख दीजिए।" यह हमारा कर्तव्य है कि हम वहां बुनियाद खड़ी करें जिनपर युवक अपने किले बना सकते हैं। यू.पी.ए. सरकार इस कार्य के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है।

179. 100 वर्ष से भी पहले एक अधीर परन्तु उत्साही युवा व्यक्ति ने सम्पूर्ण आध्यात्मिकता की खोज में अपने साथियों को इन शब्दों में फटकारा था: "हम जैसा बोते हैं, वैसा काटते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। हवा बह रही है; जिन जलयानों की पालें खुली हैं वह हवा पकड़ती हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ती हैं, परन्तु जिनकी पालें खुली नहीं होतीं, वह हवा नहीं पकड़ती। क्या यह हवा का दोष है?.....हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं।" यह रखामी विवेकानन्द के अमर वचन है। हमें अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपना भविष्य बनाना चाहिए।

180. महोदय, मैं इन शब्दों के साथ यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

एल. एम. वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2006

Budget 2006-2007

Speech of P. Chidambaram, Minister of Finance

February 28, 2006

Mr. Speaker, Sir

F. No. 2 (16)-B(D)/2006.—It is my privilege to present the Budget for the year 2006-2007.

I AN OVERVIEW OF THE ECONOMY

2. Twenty months ago, when I presented the first Budget of the UPA Government, I asked Honourable Members – and the people of this country – to walk with us on the path of honour and courage. The final report card on the first year of the UPA Government is out, and there are reasons to celebrate. According to the Central Statistical Organization (CSO), the growth rate in 2004-05 was 7.5 per cent, with the manufacturing sector growing at 8.1 per cent. More importantly, at current market prices, gross domestic saving increased to 29.1 per cent of GDP and the rate of gross capital formation increased to 30.1 per cent of GDP. I have no doubt in my mind that these results were due to the political message conveyed by the National Common Minimum Programme (NCMP); the perceptive leadership of the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh; the policy changes made by the Government; and the palpable confidence of the Indian people that their future is in safe hands.

3. I am happy to report that the prospects for 2005-06 are just as good, if not better. This year can be characterized as the best of times and the worst of times. Nature has not been kind to us. Natural calamities took a heavy toll on human lives besides causing extensive damage to crops, roads, houses, and the infrastructure. Government provided immediate interim relief; this was followed by releases from the CRF and NCCF totalling Rs. 5145.37 crore to date. Obviously, this assistance will not be enough. The Planning Commission will draw up a programme for rebuilding the damaged infrastructure, and I wish to assure the House that the Government will provide the money for rehabilitation and reconstruction.

4. It was also the best of times. Government has been able to fulfil the first NCMP obligation of ensuring a high growth rate. According to the CSO's advance

estimates, GDP growth is likely to be 8.1 per cent this year, with the manufacturing sector expected to grow at 9.4 per cent. Agricultural growth has bounced back to 2.3 per cent and, barring mining, all other sectors are performing satisfactorily. Inflation, as on February 11, 2006 was 4.02 per cent. Non-food credit is growing by over 25 per cent. A large part of the credit goes to our farmers, workers, service providers, traders and business persons, and I would urge the House to join me in saluting them.

5. The assault on poverty and unemployment continues. I believe that growth is the best antidote to poverty. The GDP growth target for the Tenth Plan was set at 8 per cent. Thanks to three years of 7.5 per cent plus growth, it is possible that the overall growth rate will be 7 per cent. In recent speeches, the Prime Minister has raised the bar to 10 per cent, and the Government is determined to take the country to that high growth path. Growth will be our mount; equity will be our companion; and social justice will be our destination.

II IMPLEMENTING THE NCMP MANDATE

6. Our success this year is due to our unrelenting emphasis on fiscal prudence through enhanced revenues and expenditure control, monetary stability and management of the external debt. However, our success should not tempt us to stray from this path, and we shall not do so.

7. One of the important NCMP obligations was to focus on agriculture: we have done so, and the output of food grains is expected to be 209.3 million tonnes, which is about 5 million tonnes more than in the previous year.

8. The NCMP mandates the Government to promote employment: while creating permanent and quality jobs in the productive sectors, for providing immediate relief to the poor, the National Rural Employment Guarantee Scheme was launched on February 2, 2006. In the current year, under a clutch of schemes including the Food for Work programme, a sum of Rs.11,700 crore is expected to be spent on rural employment.

9. The NCMP mandates the Government to enhance investment: the investment rate has increased steadily from 25.3 per cent in 2002-03 to 30.1 per cent in 2004-05. Several indicators point to continued buoyancy of capital formation in the economy.

10. The NCMP also mandates the Government to augment infrastructure. 5,083 MW of capacity will be added to power generation in 2005-06, and during the Tenth Plan period the total addition is estimated at 34,000 MW, which is a record. Until December, 2005, under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, contracts have been placed for projects spanning 95 districts and covering 41,461 un-electrified and 9,379 electrified villages. Work is on at full steam on the Golden Quadrilateral (GQ) and the North-South, East-West Corridors. As against 1.86 kms per day completed prior to May, 2004, the schemes are

progressing at the rate of 4.48 kms per day. 96 per cent of the GQ will be completed by June, 2006 and the Corridors will be completed by end 2008. There is also substantial and visible progress in improving our ports, airports and rural roads.

11. As the year draws to a close, I look back with satisfaction that the promises we made to the common citizen – the *aam admi* – have been substantially redeemed.

III BHARAT NIRMAN

12. I would like to make special mention of Bharat Nirman. It epitomizes the UPA's approach to governance. It is a paradigm shift that will enable us to use the resources thrown up by the engine of growth for building infrastructure and bringing basic amenities to rural India. Honourable Members are aware of the six components of Bharat Nirman and the ambitious targets to be achieved by the year 2009. In the first year of its implementation, 2005-06:

- Rs.944.18 crore has been released so far as grant under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and the target of 600,000 hectares of irrigation potential is expected to be created this year.
- Against the physical target of 56,270 habitations, 47,546 habitations have been covered until January, 2006 under the Accelerated Rural Water Supply Project (ARWSP)
- 5,337 habitations were connected under the rural roads programme by September, 2005, and Rs.3,749 crore has been released so far.
- 870,000 rural houses have been constructed and a sum of Rs.2,260 crore has been released till January, 2006.
- The entire allocation for rural electrification of Rs.1,100 crore has been released and the target of covering 10,366 villages is expected to be achieved in the current fiscal.
- 17,182 villages have been provided with a telephone till December, 2005 in the first year of the three year programme.

These numbers are a complete answer to those who scoffed at Bharat Nirman. We are determined to soldier on, and execute the programme in the mission mode. Since the implementation of Bharat Nirman has gathered pace, I propose to extend larger budgetary support to the programme. Including the North East component, as against Rs.12,160 crore provided in the current year, the corresponding budgetary provision will be Rs.18,696 crore in 2006-07, an increase of 54 per cent.

IV THE FLAGSHIP PROGRAMMES

13. Let me now present an overview of the Budget. Obviously, the bulk of

the resources must go to the UPA Government's eight flagship programmes: Sarva Siksha Abhiyan, Mid-day Meal Scheme, Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, Total Sanitation Campaign, National Rural Health Mission, Integrated Child Development Services, National Rural Employment Guarantee Scheme and Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.

14. In 2005-06, Gross Budgetary Support (GBS) for the Plan was Rs.143,497 crore. Of this, support to the Central Plan was Rs.110,385 crore. I propose to increase both allocations substantially. GBS for 2006-07 has been fixed at Rs.172,728 crore, representing an increase of 20.4 per cent. Out of this, the Central Plan will receive a support of Rs.131,285 crore.

15. Education and health will continue to enjoy primacy. For 2006-07, the allocation for education has been enhanced by 31.5 per cent to Rs.24,115 crore and for health and family welfare by 22.0 per cent to Rs.12,546 crore.

16. On the eight flagship programmes, the total allocation in 2005-06 was Rs.34,927 crore. In the ensuing fiscal year, the total allocation will be Rs.50,015 crore, representing an additionality of Rs.15,088 crore or 43.2 per cent.

North Eastern Region (NER)

17. To this, however, we must add the allocation of 10 per cent of the Plan Budget of each Ministry/Department for schemes and programmes in the North Eastern Region (NER). For the flagship programmes alone, this would amount to an additional allocation of Rs.4,870 crore in 2006-07. The total budget allocation for the NER is Rs.12,041 crore which includes Rs.1,350 crore provided to the Ministry of Development of North Eastern Region (DONER). From BE 2005-06 to BE 2006-07, the step up is 18 per cent.

Sarva Siksha Abhiyan

18. Sarva Siksha Abhiyan (SSA) has recorded remarkable progress in 2005-06 in terms of new schools, additional class rooms and additional teachers. Two independent surveys show that 93 per cent of the children in the age group 6-14 years are in school, and the number of children not in school has come down to about one crore. Recognizing good performance, I propose to increase the outlay for SSA from Rs.7,156 crore to Rs.10,041 crore in 2006-07. 500,000 additional class rooms will be constructed and 150,000 more teachers will be appointed.

19. In 2006-07, we shall transfer Rs.8,746 crore to the Prarambhik Siksha Kosh from the revenues raised through the education cess.

Mid-day Meal Scheme

20. 12 crore children are now covered under the Mid-day Meal Scheme, which is the largest school lunch programme in the world. I propose to enhance the allocation from Rs.3,010 crore to Rs.4,813 crore in 2006-07.

Drinking Water and Sanitation

21. The target for the current year for drinking water supply will be completed,

and 56,270 habitations and 140,000 schools will be covered. Apart from non-coverage, there is the persistent problem of slippage. The strategy to tackle both includes conservation, better operational management, and water quality monitoring and capacity building at the village level. The Government will provide non-recurring assistance of Rs.213 crore in 2006-07 for setting up district-level water testing laboratories and field-level water testing kits. I propose to increase the provision for the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission from Rs.3,645 crore to Rs.4,680 crore next year.

22. I also propose to increase the provision for the Rural Sanitation Campaign from Rs.630 crore to Rs.720 crore in 2006-07.

National Rural Health Mission

23. The National Rural Health Mission was launched on April 12, 2005. I am confident that in 2006-07 more than 200,000 Associated Social Health Activists (ASHA) will be fully functional and over 1,000 block level community health centres will provide round the clock services. I have increased the allocation for NRHM from Rs.6,553 crore to Rs.8,207 crore for the next year.

24. The WHO standard defining 'elimination of leprosy' is one case per 10,000 population. I am happy to announce that the goal of eliminating leprosy was reached in December, 2005. Continuing the vigorous immunization programme, we hope to eliminate polio too from the country by December, 2007.

Integrated Child Development Services

25. We have expanded the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme and created an additional 188,168 centres. Supplementary nutrition is the most important component of the scheme. Beginning this year, the Centre is assisting the States to the extent of 50 per cent of the actual expenditure incurred for supplementary nutrition or 50 per cent of the cost norms, whichever is less. The cost to the Centre this year is estimated at Rs.1,500 crore, and I propose to increase this assistance to Rs.1,700 crore for 2006-07. The total allocation for ICDS is being increased from Rs.3,315 crore to Rs.4,087 crore.

National Rural Employment Guarantee Scheme

26. I have already referred to the Rural Employment scheme which is the primary instrument to combat rural unemployment and hunger poverty. For 2006-07, the total allocation for rural employment will be Rs.14,300 crore. Of this, Rs.11,300 crore (including NER component) will be under the NREG Act and Rs.3,000 crore (including NER component) will be under SGRY. Since there is a legal guarantee of employment under the NREG Act, more funds will be provided according to need.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission

27. The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission was launched on December 3, 2005. For the next year, against the estimated outlay of Rs.6,250 crore, I propose to provide a grant of Rs.4,595 crore. Apart from the four projects,

including Mumbai metro rail and Bangalore metro rail, mentioned in my Budget speech last year, the projects under active consideration include projects in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat.

28. Planned urbanization can act as a spur to growth, employment and a better quality of life. Government will actively promote the establishment of new towns, preferably focussed on a specific industry, for example Information Technology, or a specific theme, for example education or health. Some projects are on the anvil in West Bengal and Karnataka.

National Social Assistance Programme

29. Old age pensions are granted under the National Social Assistance Programme (NSAP) to destitute persons above the age of 65 years at Rs. 75 per month. This is woefully inadequate. I propose to increase the pension to Rs. 200 per month. I have provided Rs. 1,430 crore for 2006-07 and additional funds, if required, will be provided during the course of the year. I would urge State Governments to make an equal contribution from their resources so that a destitute pensioner would get at least Rs. 400 per month. I also propose to work with the Department of Posts and the banks to establish, within two years, a system under which the pension will be credited directly to the account of the beneficiary in a post office or a bank.

Women and Children

30. Last year, I introduced a statement highlighting the gender sensitivities of the budgetary allocations. I was able to cover 10 demands for grants. This time, I have been able to enlarge the statement on gender budgeting to include schemes where 100 per cent of the allocation is for the benefit of women as well as schemes where at least 30 per cent of the allocation is targeted towards women. The statement now covers 24 demands for grants in 18 Ministries/Departments and five Union Territories and schemes with an outlay of Rs. 28,737 crore.

31. Furthermore, several Ministries and Departments have initiated an exercise to prepare a public expenditure profile of their budgets from a gender perspective. 32 Ministries and Departments have set up Gender Budgeting Cells.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

32. Government is committed to the welfare of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). Honourable Members will be happy to know that this Budget, like last year's, contains a separate statement on the schemes for the welfare and development of SCs and STs. On a like to like basis, the allocations for schemes benefiting only SCs and STs have been enhanced by 14.5 per cent to Rs. 2,902 crore and the allocations for schemes with at least 20 per cent allocation for SCs and STs have been enhanced by 13.9 per cent to Rs. 9,690 crore.

33. The equity contribution to the National SC Finance and Development Corporation is being increased to Rs. 37 crore and to the National Safai Karamchari Finance and Development Corporation to Rs. 80 crore in 2006-07.

Minorities

34. I propose to extend greater financial support to the organizations actively involved in the welfare of the minorities. Accordingly, I intend to double the corpus fund of the Maulana Azad Educational Foundation to Rs.200 crore.

35. I propose to contribute Rs.16.47 crore to strengthen the equity base of the National Minorities Development and Finance Corporation. In line with the Prime Minister's announcement on August 15, 2005, the Corporation will intensify its efforts to reach out to artisans and weavers living in urban and peri-urban centres, especially in districts with concentration of minorities. The programme will focus on skill enhancement, credit and techno-managerial support.

36. I propose to increase the allocation to the National Council for Promotion of Urdu Language from Rs.10 crore to Rs.13 crore.

37. Merit-cum-means based scholarships encourage students to pursue higher studies. Government will finance 20,000 such scholarships to students belonging to the minority communities. Once the scheme is finalized in 2006-07, I intend to allocate the necessary funds.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme

38. The initial results of the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme launched in 2004 are encouraging. 1,000 new residential schools for girls from SC, ST, OBC and minority communities will be opened in 2006-07. I have provided Rs.128 crore, and I have agreed to provide an additional sum of Rs.172 crore during the year. I propose to provide a further incentive to the girl child who passes the VIII Standard Examination and enrols in a secondary school. A sum of Rs.3,000 will be deposited in her name, and she would be entitled to withdraw it on reaching 18 years of age.

39. Government has shifted the emphasis from sheer 'quantity' to the 'quality' of the outcome of the various social sector programmes. To ensure value for public expenditure, an Outcome Budget was presented on August 25, 2005. Government intends to present a Performance Budget on the first Outcome Budget before the end of the Budget Session. The Outcome Budget for 2006-07 will be placed before this House by March 17, 2006. This new approach underscores our resolve to ensure that the intended services in the right quantity and quality are delivered to the *aam admi*.

V INVESTMENT

40. There is an investment boom in the country and it is necessary to maintain the confidence of investors. It appears that India is catching up with the high investment rates of East Asia and China. Honourable Members will notice presently that, in every sector, the attempt is to promote more investment.

41. Government is committed to a strong and effective public sector. Public Sector Enterprises (PSEs) have, through internal and extra-budgetary resources, investment plans amounting to Rs.122,757 crore in 2006-07. I am happy to announce that Government will provide equity support of Rs.16,901 crore and loans of Rs.2,789 crore to Central PSEs (including Railways). Besides, I wish to point out that in the two years of this Government, we have infused Rs.1,180 crore in cash and made non-cash sacrifices of Rs.2,566 crore to restructure ten PSEs, including Indian Telephone Industries Limited and Heavy Engineering Corporation Limited.

42. We believe that there is considerable scope for developing India as a hub for the gems and jewellery industry. I, therefore, propose to constitute an expert body that will look into the potential of this sector and the prevalent taxation practices in India and abroad, and make its recommendations in this behalf. I am sure this announcement will be welcomed by Non Resident Indians who are looking to India as the place for future expansion and growth.

43. Foreign Direct Investment (FDI) continues to play an important role. We have the opportunity to make India a manufacturing hub for textiles, automobiles, steel, metals, petroleum products etc. for the world market. In calendar 2005, up to November, 2005, FDI is estimated at \$ 4 billion, without counting reinvested earnings and other capital. I am confident that recent policy changes will attract more foreign investment into the country, especially in infrastructure.

VI AGRICULTURE

44. Let me now turn to the productive sectors of the economy. As always, our Government's focus is on agriculture. Assured irrigation, credit, diversification and creating a market for agricultural products are the thrust areas.

Irrigation

45. Out of an outlay of Rs.4,500 crore under AIBP in 2005-06, the grant component is Rs.1,680 crore. The States are expected to spend about Rs.2,520 crore from their resources, and 25 projects are expected to be completed before the end of the year. The outlay for 2006-07 has been increased to Rs.7,121 crore, and the Central Government will support the programme through a grant of Rs.2,350 crore. The Ministry of Water Resources will revamp the Command Area Development Programme to allow participatory irrigation management through water users' associations.

46. The programme for repair, renovation and restoration of water bodies is being implemented through pilot projects in 23 districts in 13 States. The design of the programme has been finalized in consultation with the States. 20,000 water bodies with a command area of 1.47 million hectares have been identified in the first phase. The estimated cost is Rs.4,481 crore. The funding pattern (Centre, States and external assistance) has been finalized, and I intend to seek,

and receive, funds from multi-lateral agencies. The participating State Government will be requested to sign a memorandum of understanding and the water bodies in that State will be taken up for repair, renovation and restoration in 2006-07.

Credit

47. Farm credit increased to Rs.125,309 crore in 2004-05 (well above the target) and is again expected to cross the target of Rs.141,500 crore set for the current year. I propose to ask the banks to increase the level of credit to Rs.175,000 crore in 2006-07 and also add another 50 lakh farmers to their portfolio. We shall not only achieve but exceed the target of doubling farm credit in three years. Since tenant farmers are not adequately served, I have asked the banks to open a separate window for self-help groups or joint liability groups of tenant farmers and ensure that a certain proportion of the total credit is extended to them. I intend to monitor closely progress in this behalf.

48. I am aware of the severe difficulties faced by farmers in the last two years. Ours is a compassionate Government. I also have severe fiscal constraints. When faced with a dilemma, I usually turn to my favourite poet-philosopher, Saint Tiruvalluvar. Writing over 2,000 years ago, he said:

“Karumam Sidhaiyamal Kannoda Vallarku

Urimai Udaithu Iv Ulagu”

(The world is his who does his job

With compassion)

I am prepared to go the extra mile to come to the aid of our farmers. To begin with, I propose to grant some relief to the farmers who have availed of crop loans from scheduled commercial banks, RRBs and PACS for Kharif and Rabi 2005-06. Accordingly, an amount equal to two percentage points of the borrower's interest liability on the principal amount up to Rs.100,000, will be credited to his/her bank account before March 31, 2006. I have provided a sum of Rs.1,700 crore for this purpose. I hope the House will welcome this exceptional gesture of the Government.

49. For our farmers, I have more. Farmers obtain short-term credit from the cooperative credit structure and Regional Rural Banks (RRBs), with refinance from NABARD. Increasingly, scheduled commercial banks are also lending more to farmers. It is my intention to ensure that NABARD continues to provide refinance at an economical rate, so that the farmer ultimately gets the loan at a reasonable rate. Accordingly, after giving anxious consideration to market conditions, Government has decided to ensure that the farmer receives short-term credit at 7 per cent, with an upper limit of Rs.300,000 on the principal amount. This would require a certain level of subvention to NABARD. I propose to give the subvention. This policy will come into force with effect from Kharif 2006-07, and I shall make a detailed statement in due course.

50. The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) has so far disbursed funds in 11 tranches. RIDF XI sanctions have touched a level of Rs.7,301 crore as on January 31, 2006. A special feature this year has been that Rs.346 crore has been sanctioned to the North Eastern States. This sum is likely to touch Rs.600 crore by the year end. Keeping in view the expanding requirements for creating rural infrastructure, I propose to increase the corpus of RIDF XII to Rs.10,000 crore, and I urge State Governments to make the best use of these funds.

51. I also propose to allow specified projects under the Public Private Partnership (PPP) model to access RIDF funds.

52. The rural roads component of Bharat Nirman requires large funds. Hence, I propose to open a separate window under RIDF XII for rural roads with a corpus of Rs.4,000 crore during 2006-07.

Agricultural Insurance

53. The National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) will be continued in its present form for Kharif and Rabi 2006-07.

Plantation Sector

54. In continuation of the announcement in the last Budget to introduce a 15 year programme for massive re-plantation and rejuvenation of tea, Ministry of Commerce has proposed to set up a Special Purpose Tea Fund. While the details are being worked out, to signal my support to the idea, I propose to make a leveled contribution every year to the Fund. For 2006-07, the contribution is expected to be Rs.100 crore. When established, the Fund will benefit growers in the tea growing States including Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Uttaranchal.

Micro Finance

55. I had proposed major initiatives in respect of micro finance in the last Budget. RBI has since issued guidelines to enable banks to appoint banking correspondents and banking agents. A window to access ECB funds has also been opened. A Bill to provide a formal statutory framework for the promotion, development and regulation of the micro finance sector will be introduced in this session.

56. The Self Help Group (SHG) movement is making rapid strides. In the two years of the UPA Government, we have credit-linked 801,000 SHGs. The credit disbursed to these SHGs is approximately Rs.4,863 crore. I propose to ask the banking sector to credit-link another 385,000 SHGs in 2006-07. I shall also ask NABARD to open a separate line of credit for financing farm production and investment activities through SHGs.

57. The findings of the NSS 59th Round (2003) reveal that out of the total number of cultivator households only 27 per cent receive credit from formal sources and 22 per cent from informal sources. The remaining households, mainly

small and marginal farmers, have virtually no access to credit. With a view to bringing more cultivator households within the banking fold, I propose to appoint a Committee on Financial Inclusion. The Committee will be asked to identify the reasons for exclusion, and suggest a plan for designing and delivering credit to every household that seeks credit from lending institutions.

Horticulture and Fisheries

58. The PPP model will be employed to set up model terminal markets in different parts of the country. A sum of Rs.150 crore has been earmarked for this purpose in 2006-07 under the National Horticulture Mission. A Central Institute of Horticulture will be established in Nagaland. The National Fisheries Development Board will be constituted shortly.

VII MANUFACTURING

Employment

59. The two sectors which have the potential to create a large number of jobs are manufacturing and services. In manufacturing, we have identified some industries which, with appropriate incentives, can throw up huge job opportunities. These include textiles, food processing, petroleum, chemicals and petrochemicals, leather, and automobiles. In services, tourism and software can offer a large number of jobs.

Textiles

60. The last two Budgets have created an enabling environment for the growth of the textile industry, especially cotton textiles. There has been an encouraging response to the Technology Upgradation Fund (TUF) scheme. I propose to enhance the allocation from Rs.435 crore to Rs.535 crore next year. The Scheme for Integrated Textiles Parks (SITP) was launched in October 2005 with the intention of creating 25 textile parks. As on date, 7 parks have been sanctioned and 10 parks have been identified for development. I propose to provide Rs.189 crore for this scheme.

61. Government proposes to launch the Jute Technology Mission in 2006-07 to harness the potential of the golden fibre. A National Jute Board will be established. I propose to make a token provision with the assurance that the funds required will be made available once the outlay is finalized.

Handlooms

62. Several schemes, including schemes for life insurance and health insurance, were announced in the last Budget for the handloom sector. They are being implemented. The Cluster Development approach will continue. It is proposed to cover an additional 100 clusters at a cost of Rs.50 crore in 2006-07. Yarn depots will be established in different parts of the country to ensure uninterrupted supply of yarn to weavers. Just as 'woolmark' has gained recognition, it is proposed to launch a 'handloom' mark. A scheme similar to

TUFS will be introduced for the handloom sector to provide interest subsidy on term loans. I propose to increase the provision for the handloom sector from Rs.195 crore to Rs.241 crore next year.

Food Processing Industry

63. Recognizing the enormous benefits that the food processing industry can bring to agriculture and job creation, and to consumers, food processing will be treated as a priority sector for bank credit. NABARD will create a separate window with a corpus of Rs.1,000 crore for refinancing loans to the sector, especially for agro-processing infrastructure and market development. Government will also set up the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management. The Paddy Processing Research Centre at Thanjavur will be developed into a national-level institute.

Petroleum, Chemicals and Petro-chemicals

64. Petroleum, chemicals and petro-chemicals (PC&P) is a sector with potential for large investment and employment. In order to promote investment in this sector, Government has set up a Task Force to facilitate the development of large PC&P Investment Regions. World class developers and investors are being associated with the Task Force. It is expected that in 2006-07 at least three such Investment Regions will be developed.

Information Technology

65. With the spread of Information Technology (IT) and IT Enabled Services (ITES), the time is ripe to make India a preferred destination for the manufacture of semi-conductors and other high technology IT products including Wafer; Assemble, Test and Manufacture of Semi-conductors; Flat LCD/OLED/Plasma Panel Displays; and Storage Devices. To achieve this goal the Ministry of Information Technology will announce a policy shortly. I propose to use the existing vehicles of viability gap funding and the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) to create a window to provide equity participation and/or viability gap funding to the new ventures. The window will be open for three years in order to accelerate investment.

Small and Medium Enterprises

66. The introduction of the Small and Medium Enterprises (Development) Bill and the policy on credit announced on August 10, 2005 have, I believe, triggered a change in the mindset of small and medium entrepreneurs. The new thrust is towards up-scaling the size and technological upgradation. After due consultation with the stakeholders and on the recommendation of the Advisory Committee, the Ministry of Small Scale Industries has identified 180 items for dereservation.

67. In order to give a fresh impetus to lending by the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), I propose to:

- Recognize SMEs in the services sector, and treat the small scale enterprises in the services sector on par with the small scale enterprises in the manufacturing sector;
- Raise the corpus of the Credit Guarantee Fund from Rs.1,132 crore at end-March 2006 to Rs.2,500 crore in five years. In 2006-07, I propose to provide a sum of Rs.118 crore;
- Advise Credit Guarantee Trust for Small Industries (CGTSI) to reduce the one time guarantee fee from 2.5 per cent to 1.5 per cent for all loans; and
- Extend insurance cover to approximately 30,000 borrowers, identified as chief promoters, under the CGTSI. The sum assured would be Rs.200,000 per beneficiary and the premium will be paid by CGTSI.

68. The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has finalized a five-year National Manufacturing Competitiveness Programme. Ten schemes have been drawn up including schemes for promotion of ICT, mini tool rooms, design clinics and marketing support for SMEs. Implementation will be in the PPP model, and financing will be tied up during the course of the next year.

Cluster Development

69. The Cluster Development model can be usefully adopted not only to promote manufacturing but also to renew industrial towns and build new industrial townships. The model is now being implemented, in one form or other, in nine sectors falling under different Ministries. The sectors include khadi and village industries, handlooms, handicrafts, textiles, agricultural products and medicinal plants. It would be advantageous to empower a group to oversee cluster development and monitor progress. Hence, the Prime Minister has decided to constitute an Empowered Group of Ministers who will lay down the policy for cluster development and oversee the implementation.

VIII SERVICES SECTOR

Tourism

70. Foreign tourist arrivals increased to 3.92 million in 2005. It is still a fraction of India's potential. During 2006-07, Ministry of Tourism will:

- Take up for development 15 tourist destinations and circuits following an integrated area development approach;
- Identify 50 villages with core competency in handicrafts, handlooms and culture, close to existing destinations and circuits, and develop them for enhancing tourists' experience; and
- Establish 4 new institutes of hotel management in the States of Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand and Uttarakhand.

I propose to increase the Plan allocation from Rs.786 crore to Rs.830 crore in 2006-07.

Foreign Trade

71. Merchandise exports are growing at the rate of over 18 per cent in the current year. Imports are high, but they are welcome because they are a sign of enhanced capital investment and industrial activity. Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance have worked together to create an environment that is supportive of our exporters, and we are determined to double our share in world exports to 1.5 per cent by the year 2008-09.

IX INFRASTRUCTURE

Telecommunication

72. The telecommunication sector in India is recording one of the fastest growth rates in the world. Tele-density stood at 11.75 per hundred at end-January, 2006. The ambitious target is to reach 250 million connections by December, 2007, and I am confident of success. I propose to provide Rs.1,500 crore from the Universal Services Obligation Fund in 2006-07.

73. More than 50 million rural connections will be rolled out in three years and, thereafter, a connection will be available on demand. The digital divide between rural India and urban India will be bridged. In order to extend financial support to infrastructure for cellular telephony in rural areas, the Minister of Communications will bring a Bill in the Budget session to amend the Indian Telegraph Act.

Power

74. Power generation in 2005-06 has so far shown a modest growth of 4.7 per cent because of shortage of fuel, mainly LNG and coal. The demand-supply mismatch continues. More efforts are required to augment capacity in generation, transmission and distribution. 82 projects are under construction and, when completed in one to three years, will add 33,000 MW of capacity in the public sector and 6,500 MW of capacity in the private sector. Of these, about 15,000 MW will come on stream by March 31, 2007.

75. Ministry of Power has invited bids for five ultra mega power projects of 4,000 MW each, of which two will be pit-head (in Chhattisgarh and Madhya Pradesh) and three will be coastal (in Gujarat, Karnataka and Maharashtra). It is our intention to award these projects before December 31, 2006.

76. Capacity addition alone is not enough; we need deep and durable reforms in transmission and distribution. In order to create an enabling and empowered framework to carry out these reforms, the Prime Minister will establish an Empowered Committee of Chief Ministers and Power Ministers.

77. A target of 3,075 MW of installed capacity for the Tenth Plan was fixed for non-conventional energy sources, including wind power. By December 31, 2005, that target had been exceeded and 3,650 MW of capacity installed. I propose to provide a sum of Rs.597 crore next year for non-conventional energy resources.

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana

78. All States have signed memoranda of understanding to implement the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana. 10,000 villages will be electrified in the current year and, in 2006-07, 40,000 more villages will be electrified. The key to the success of this programme is the engagement of franchisees and proper commercial and contractual arrangements for distribution, billing and collection.

Coal

79. A comprehensive review of the coal policy is underway. This year, 45 coal blocks have been allotted for captive consumption to the power, cement and steel sectors and to the State Governments. After reserving blocks for Coal India Limited and its subsidiaries for the period up to 2012, it has been decided to de-block coal reserves of 20 billion tonnes for power projects. The definition of captive consumption will also be amended to allow coal mining by producers with firm supply contracts with steel, cement and power companies. The capacity of Central Mines Planning and Development Institute Limited (CMPDIL) to drill in order to prove reserves is now only 200,000 metres per annum, and this will be expanded substantially.

Petroleum

80. Energy security is high on the Government's agenda. In five rounds of the New Exploration Licensing Policy (NELP), 110 production sharing contracts have been awarded. Ministry of Petroleum and Natural Gas has now made its biggest offer under NELP VI. 55 blocks and an area of 355,000 sq kms, which is thrice as large as the previous round, have been offered. Besides investment in the upstream and downstream segments, we are encouraging investment in refining, pipelines and green fuel projects. In the refinery sector alone, an investment of Rs.22,000 crore is expected in the next few years.

Road Transport

81. The National Highways Development Programme (NHDP) continues to make impressive progress. The highest ever number and value of contracts were awarded in calendar 2005. I propose to enhance the Budget support for NHDP from Rs.9,320 crore to Rs.9,945 crore in 2006-07.

82. A special accelerated road development programme for the North Eastern region at an estimated cost of Rs.4,618 crore has been approved. For 2006-07, I propose to provide a sum of Rs.550 crore for this programme.

83. Government has also decided to develop 1,000 kms of access-controlled Expressways. These will be on new alignment and built on the Design, Build,

Finance and Operate (DBFO) model. The sections that have been identified are Vadodara-Mumbai, Delhi-Chandigarh, Delhi-Jaipur, Delhi-Meerut, Delhi-Agra, Bangalore-Chennai and Kolkata-Dhanbad. The concessionaires will be selected through an international competitive bidding process.

84. National Highway Authority of India (NHAI) will be restructured and made more effective. It will be made into a multi-disciplinary body with the capacity to handle a large number of PPP projects. New skill areas in planning and quality assurance, standardization, arbitration, road-safety and R&D will be created.

Maritime Development

85. Honourable Members are aware that the National Maritime Development Programme (NMDP) has been approved by the Government. The port sector alone will require Rs.55,804 crore. Work is in progress in 101 projects covering, inland waterways, shipping and ports which include deepening of channels in Kandla, JNPT and Paradip. I propose to increase the Plan allocation for the Department of Shipping by 37 per cent to Rs.735 crore.

86. A deep draft port is required in the eastern part of the country. I am happy to announce that it is proposed to carry out a detailed study to identify a suitable location for a new deep draft port in West Bengal. The existing National Institute of Port Management, Chennai, has been renamed as the National Maritime Academy, and it is proposed to upgrade it into a Central University under an Act of Parliament. The University will have regional campuses at Mumbai, Kolkata and Visakhapatnam.

87. The India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) has been incorporated, and the first proposal for funds has been received. Several proposals have been received for viability gap funding for PPP projects. In-principle approval has been granted to three road projects in Gujarat and a final decision is likely to be taken before March 31, 2007.

X FINANCIAL SECTOR

Banking, Insurance and Pensions

88. As part of the reforms in the banking sector introduced in 1993-94, capital was infused in the banks by issue of special securities. To date, Government has injected Rs.16,809 crore into nationalised banks. Adding the perpetual securities issued earlier, the total net capital support stands at Rs.22,808 crore. Thanks to the capital support, a sound banking sector meeting international norms has emerged. We have reached a stage when we can wind up the special arrangements between Government and the banks. Accordingly, after consulting the RBI, I propose to unwind the special securities through conversion of these non-tradable special securities into tradable, SLR Government of India dated securities. This will facilitate increased access of the banks to additional resources for lending to the productive sectors in the light of the increasing credit needs of the economy.

89. Honourable Members are aware that the K.P. Narasimhan Committee was appointed to recommend a comprehensive law on insurance. The report of the committee has been received, and is being examined by the Insurance Regulatory and Development Authority and the Government. I intend to introduce a comprehensive Bill on insurance in 2006-07.

90. Important Bills to amend the banking laws and for setting up the Pension Fund Regulatory and Development Authority are before Parliament. The Standing Committee on Finance has recommended these Bills. I would urge Honourable Members to cooperate with the Government and pass these Bills.

Capital Market

91. In recent months, the capital market has attracted a great deal of attention. The measures taken in the last year-and-a-half have deepened, broadened and strengthened the market. It is necessary to take more measures. Hence, I propose to

- Increase the limit on FII investment in Government securities from \$ 1.75 billion to \$ 2 billion and the limit on FII investment in corporate debt from \$ 0.5 billion to \$ 1.5 billion;
- To raise the ceiling on aggregate investment by mutual funds in overseas instruments from \$ 1 billion to \$ 2 billion and to remove the requirement of 10 per cent reciprocal share holding;
- To allow a limited number of qualified Indian mutual funds to invest, cumulatively up to \$ 1 billion, in overseas exchange traded funds; and
- To set up an investor protection fund under the aegis of SEBI, funded by fines and penalties recovered by SEBI. This will bolster confidence among retail investors who should be the key drivers of the capital market.

Consultations have been held in this behalf with RBI and SEBI, who will issue the guidelines in due course.

92. RBI had introduced the anonymous electronic order matching trading module called NDS-OM on its Negotiated Dealing System. In the first phase, RBI-regulated entities, banks and primary dealers were allowed to trade on the system. The system has now been extended to all insurance entities. In view of the encouraging response of market participants and to further deepen the Government securities market, it is proposed to extend access to qualified mutual funds, provident funds and pension funds.

93. In my Budget speech last year, I had appointed a high-level expert committee on corporate bonds. The committee has submitted its report and Government has accepted the recommendations. We shall now take steps to create a single, unified exchange-traded market for corporate bonds.

XI OTHER PROPOSALS

Research and Development

94. Our outstanding human resources have the capacity to make India a Knowledge Society. Government accords high importance to research and development. The National Agricultural Innovation Project for research at the frontiers of agricultural science is expected to receive multilateral assistance shortly, and will be launched in July, 2006.

95. The National S&T Entrepreneurship Board has set up a number of Technology Business Incubators with seed funding from the Technology Development Board. Government will be happy to provide enabling concessions to the incubatee-entrepreneurs.

Institutions of Excellence

96. Last year, I made a beginning with an unprecedented grant of Rs.100 crore to the Indian Institute of Science (IISc), Bangalore to help develop it into a world-class institution. I am happy to report that the IISc has obtained approval for an ambitious programme of modernization, and is implementing the same. This year, I must recognize another historical event. Three great Universities have entered their 150th year. These are the University of Calcutta, the University of Mumbai and the University of Madras. I propose to mark the beginning of the 150th year celebrations with a grant of Rs.50 crore to each University for a specified research department or a research programme in that University. On the conclusion of the year, I intend to make another grant of Rs.50 crore to each of them.

97. I propose to make the special grant of Rs.100 crore for an institution of excellence to a distinguished institution, the Punjab Agricultural University, Ludhiana, in acknowledgement of its pioneering contribution to the green revolution.

98. If agriculture is an ancient Indian skill, biotechnology is the new frontier that India will conquer. In order to foster research and development in biotechnology, the Ministry of Science and Technology has decided to accord the status of an autonomous National Institute to the Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology, Tiruvananthapuram, Kerala.

Skills Development

99. Honourable Members will recall that Government has taken up a programme to upgrade 500 ITIs over five years. 100 ITIs are now covered with the help of the private sector. Assistance has been sought from multilateral agencies to cover the remaining 400 ITIs. I propose to allocate Rs.97 crore for this purpose in 2006-07. The Skills Development Initiative (SDI) announced last year has been taken up through a PPP scheme, and I propose to make an initial provision of Rs.10 crore.

Backward Regions Grant Fund

100. Upon the establishment of a Backward Regions Grant Fund, a sum of Rs.1,156 crore has been disbursed so far in the current year to the districts identified as backward as well as under Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY). The Fund is being placed under the administrative control of the Ministry of Panchayati Raj, and I propose to allocate Rs.5,000 crore in 2006-07.

Jammu and Kashmir

101. Government will continue to provide special assistance to Jammu and Kashmir. The State Plan for 2006-07 has been fixed at Rs.2,300 crore. In addition, I propose to provide a sum of Rs.848 crore for the J&K Reconstruction Plan, including Rs.230 crore for the Baglihar Project. I also propose to provide special central Plan assistance of Rs.1,300 crore to enable the State to undertake reforms in the power sector.

Defence Expenditure

102. Government has fulfilled the long-standing need of retired Armed Forces Personnel Below Officer Rank (PBOR) for better pensionary benefits. About 12 lakh PBOR have benefited to the tune of Rs.460 crore with effect from January 1, 2006, and I am sure the House will welcome this decision.

103. In view of the enhanced expenditure on modernisation of defence forces, I propose to increase the allocation for defence from Rs. 83,000 crore to Rs. 89,000 crore in 2006-07, and this will include Rs. 37,458 crore for capital expenditure.

e-Governance

104. The National e-Governance Plan will be approved shortly, and 25 projects, in mission mode, will be launched in 2006-07. Among them is Project MCA-21 to enable companies to file returns electronically and a project for setting up common service centres and assigning unique ID to BPL families. It is Government's intention to bring a number of services online, in a web-based mode, including applications under the Right to Information Act, applications for house sites, ration cards, transfers of teachers, inclusion in the electoral roll, filing of police complaint, and issue of birth/death certificates and copies of land records.

Celebrating History and Heritage

105. In 2007, we will celebrate the 150th anniversary of the First War of Indian Independence, an event that shaped the destiny of the nation. To ensure that the event is observed in a befitting manner, I propose to make a provision of Rs.10 crore for preparatory activities.

106. Two Gandhian institutions, the National Gandhi Museum, Rajghat and the Kasturba Gandhi National Memorial Fund, Indore deserve support. I intend to provide Rs.5 crore each to the corpus of these institutions in 2006-07.

107. I am happy to inform the House that Kuttiyattam, Vedic Chanting and Ramlila have been declared 'Oral and Intangible Heritage of Humanity' by the UNESCO. These old art forms and oral traditions need to be safeguarded. Pending drawing up a detailed scheme, I propose to make an initial provision of Rs.5 crore in 2006-07.

XII FISCAL CONSOLIDATION

Twelfth Finance Commission

108. The recommendations of the Twelfth Finance Commission (TFC) are being implemented. Cumulatively, State loans amounting to Rs.103,710 crore have been consolidated so far. Under the new scheme of tax devolution, Rs.94,402 crore will be released as the States' share in the current year compared to Rs.78,595 crore in 2004-05. As regards grants-in-aid, the amounts granted in 2004-05 and 2005-06 (RE) are Rs.12,081 crore and Rs.25,134 crore respectively. In 2006-07, both the tax devolution and the grants will be substantially higher. The States have never been so well provided, as you will find from the Budget papers.

109. I may add that I have made appropriate provision in the Budget for debt consolidation and relief. I have also provided Rs.3,000 crore towards compensation for VAT losses, if any, in 2006-07.

Subsidies

110. The issue of subsidies is proving to be a divisive one, but I would urge Honourable Members that it is imperative that we make progress on this front if we are serious about targeting subsidies at the poor and the truly needy. My Ministry has held extensive discussions with stakeholders on three major subsidies, namely, food, fertilizer and petroleum. We have also sought the views of the general public. Working groups/committees have gone into the question of fertilizer and petroleum subsidies, the latest being the Dr. C. Rangarajan Committee. I would urge Members to help the Government evolve a consensus on the issue of subsidies.

Gross Budgetary Support and Gross Fiscal Deficit

111. Mr. Speaker, Sir, please allow me to draw your attention to two path breaking developments on the fiscal front. Firstly, the strategy of enhanced revenue mobilization through reasonable rates, better compliance and widening of the tax base is yielding tangible results. For the Centre, the gross tax-GDP ratio, after rising from 9.2 per cent in 2003-04 to 9.8 per cent in 2004-05, has increased further to 10.5 per cent in 2005-06 (RE). Government estimates that, through better tax administration, it will increase to 11.2 per cent in 2006-07(BE).

112. Secondly, the year 2004-05, for which the actuals are available, has proved to be a turning point. After 20 years, the Gross Fiscal Deficit is less than the Gross Budgetary Support for Plan in that year. What does this mean? This means

that Government is not financing the Plan entirely through borrowing. Whether this trend continued in 2005-06 will be known only after the actuals are available. However, in the BE for 2006-07, I have been able to confine the gross fiscal deficit to a number much smaller than the gross budgetary support for the Plan.

113. Last year, reluctantly, I pressed the 'pause' button on fiscal correction. I had estimated the revenue deficit for 2005-06 at 2.7 per cent and the fiscal deficit at 4.3 per cent. I am happy to report that I have been proved wrong. We have improved upon both measures. According to revised estimates, the revenue deficit for the current year will be only 2.6 per cent and the fiscal deficit will be only 4.1 per cent.

XIII BUDGET ESTIMATES FOR 2006-07

114. I turn to the Budget Estimates for the next fiscal.

Plan Expenditure

115. Plan expenditure for 2006-07 is estimated at Rs.172,728 crore, up by 20.4 per cent. As a proportion of total expenditure, Plan expenditure has increased from 26.6 per cent in 2004-05 to 28.3 per cent in 2005-06 (RE) and further to 30.6 per cent in 2006-07 (BE). This points to the improvement in the quality of Government expenditure.

Non-Plan Expenditure

116. Non-Plan expenditure in 2006-07 is estimated to be Rs.391,263 crore. The increase of 5.5 per cent over non-plan expenditure in 2005-06 (BE) is due to normal growth and is one the smallest in recent years.

Revenue Deficit and Fiscal Deficit

117. Mr. Speaker, Sir, in the Budget Estimates for 2006-07, the total expenditure is estimated at Rs.563,991 crore. I estimate total revenue receipts of the Central Government at Rs.403,465 crore and the revenue expenditure at Rs.488,192 crore. Consequently, the revenue deficit is estimated at Rs.84,727 crore which is 2.1 per cent of the GDP. The fiscal deficit is estimated at Rs. 148,686 crore, which is 3.8 per cent of the GDP. I believe that I have redeemed my promise that the process of fiscal correction will be resumed in 2006-07.

PART-B**XIV TAX PROPOSALS**

118. Mr. Speaker, I shall now present my tax proposals. In the UPA Government's first Budget, and more so in the second, I had attempted significant tax reforms. The results are encouraging. In 2004-05, gross tax revenues (provisional actuals) increased by 19.9 per cent over the actuals of the previous year and, according to Revised Estimates, in 2005-06, they are expected to increase by 21.4 per cent over the provisional actuals of the previous year. These figures confirm our belief that we should keep our tax rates moderate and stable.

Indirect Taxes

119. I shall begin with my proposals on indirect taxes. Firstly, customs duties.

120. In line with the Government's policy of reducing customs duties, I propose to reduce the peak rate for non-agricultural products from 15 per cent to 12.5 per cent. I believe that we are now only a short distance away from East Asian rates.

121. As the peak rate comes down, there is a need to reduce the duty on raw materials and intermediates.

122. The duty on primary steel is at 5 per cent. I propose to reduce the duty on alloy steel and primary and secondary non-ferrous metals from 10 per cent to 7.5 per cent. This will also be the rate of duty for ferro alloys.

123. In 2004-05, in view of the high international prices of steel, I had reduced the import duty on steel melting scrap to zero. With prices of steel coming down, I propose to restore the duty to 5 per cent and bring it on par with primary steel.

124. The duty on mineral products is now 15 per cent. I propose to reduce it to 5 per cent, with a few exceptions.

125. I also propose to reduce the duty on ores and concentrates from 5 per cent to 2 per cent.

126. Refractories attract a duty of 10 per cent. A number of materials required for manufacture of refractories are also at 10 per cent or higher rates. I propose to reduce these duties to 7.5 per cent.

127. Basic inorganic chemicals are crucial raw materials. I propose to reduce the duty from 15 per cent to 10 per cent. On basic cyclic and acyclic hydrocarbons and their derivatives, I propose to bring down the rate to 5 per cent. I also propose to reduce the duty on catalysts from 10 per cent to 7.5 per cent.

128. Plastics are important raw materials. Hence, I propose to reduce the duty on major bulk plastics like PVC, LDPE and PP from 10 per cent to 5 per cent. Simultaneously, the duty on naphtha for plastics will be reduced to nil.

129. I propose to reduce the duty on styrene, EDC and VCM which are raw materials for plastics to 2 per cent.

130. I propose to give some concessions to vital drugs. I propose to reduce the customs duty on 10 anti-AIDS and 14 anti-cancer drugs to 5 per cent. I also propose to reduce the duty on certain life saving drugs, kits and equipment from 15 per cent to 5 per cent. These drugs will also be exempt from excise duty and countervailing duty (CVD).

131. Packaging machines serve a wide variety of industries, including food processing. I propose to reduce the duty on packaging machines from 15 per cent to 5 per cent.

132. I propose to extend the concessional project rate of 10 per cent to pipeline projects for transportation of natural gas, crude petroleum and petroleum products.

133. Honourable Members would recall that last year I had taken the power to impose a CVD on all imports to compensate for State level taxes. This levy was applied only to imports of ITA bound items and their inputs, except IT software. After the introduction of VAT in most States, I have received representations from trade and industry that this levy should be extended to all imports. The argument is persuasive, and I propose to impose a CVD of 4 per cent on all imports with a few exceptions. Full credit of this duty will be allowed to manufacturers of excisable goods.

134. In order to protect the domestic vanaspati industry, I propose to increase the customs duty on vanaspati to 80 per cent, the rate applicable to crude palm oil.

135. Export oriented units (EOUs) are allowed to clear their goods to the Domestic Tariff Area (DTA) at a concessional rate. With declining import duties, DTA units and EOUs should have a level playing field as regards excise duty or CVD. Hence, I propose to adjust the duty rates on clearances by EOUs to the DTA at 25 per cent of basic customs duty plus excise duty on like goods. This will still give the EOU a tariff advantage or, at any rate, in most cases, it will be on par with a DTA unit.

136. Finally, I have an important proposal that involves both excise and customs duties. Cotton textile industry has greatly benefited from the relief granted two years ago. The man-made textile industry is a growth- and employment-driver. It deserves encouragement. Hence, I propose to reduce the excise duty on all man-made fibre yarn and filament yarn from 16 per cent to 8 per cent. Simultaneously, I propose to reduce the import duty on all man-made fibres and yarns from 15 per cent to 10 per cent. Consequently, the import duty on raw materials such as DMT, PTA and MEG will also be reduced from 15 per cent to 10 per cent. The import duty on paraxylene is proposed to be reduced to 2 per cent.

137. I have a few proposals on the excise side. I reiterate that it is our intention to converge all rates at the CENVAT rate which is now at 16 per cent. There are only two items – aerated drinks and cars – that still attract the higher rate of 24 per cent. I propose to correct this substantially. I propose to reduce the excise

duty on aerated drinks to 16 per cent. On cars, I propose to reduce the excise duty to 16 per cent, but only for small cars. A small car, for this purpose, will mean a car of length not exceeding 4,000 mm and with an engine capacity not exceeding 1,500 cc for diesel cars and not exceeding 1,200 cc for petrol cars. I am confident that industry will seize the opportunity to make India a hub for the manufacture of small and fuel-efficient cars.

138. I propose to impose an 8 per cent excise duty on packaged software sold over the counter. Customized software and software packages downloaded from the internet will be exempt from this levy.

139. I propose to fully exempt from excise duty DVD Drives, Flash Drives and Combo Drives.

140. Many food items, including packaged items, attract nil excise duty. With a view to giving a fillip to the food processing industry, I propose to fully exempt from excise duty condensed milk, ice cream, preparations of meat, fish and poultry, pectins, pasta and yeast. Excise duty on ready-to-eat packaged foods and instant food mixes, like *dosa* and *idli* mixes, will be reduced from 16 per cent to 8 per cent.

141. Since leather and footwear are thrust sectors, I propose to exempt from excise duty two vegetable tanning extracts, namely, quebracho and chestnut. Footwear carrying a retail sale price up to Rs.250 is already exempt from excise duty. I propose to reduce excise duty on footwear with a retail sale price between Rs.250 and Rs.750 from 16 per cent to 8 per cent.

142. At present LPG stoves up to a value of Rs.2,000 attract excise duty of 8 per cent. I propose to extend the concessional rate to all LPG stoves without any value limit.

143. To promote the use of energy efficient lamps, I propose to reduce the excise duty on compact fluorescent lamps from 16 per cent to 8 per cent.

144. I propose to remove rate differences between different kinds of tableware and kitchenware. Consequently, glassware will attract excise duty of 16 per cent on par with ceramicware and plasticware.

145. Paper finds widespread use in education as well as in packaging. In order to encourage capacity addition, I propose to reduce excise duty on specified printing, writing and packing paper from 16 per cent to 12 per cent.

146. Domestically produced petroleum crude is subject to a cess under the Oil Industries Development Act. The rate of Rs.1,800 per metric tonne was fixed in 2002. After consulting the Ministry of Petroleum and Natural Gas, I propose to increase the cess to Rs.2,500 per MT. I have been assured that this increase will be absorbed by the oil producing companies and have no impact on retail prices of petroleum products.

147. There are two requests from trade and industry. I had exempted computers from excise duty in order to boost the use of computers. That purpose has been largely served. Domestic manufacturers have sought re-imposition of excise duty at 12 per cent in order to enable them to take CENVAT credit as well as to face competition from imports. I propose to accept the request. Since the 12 per cent excise duty will be eligible for full input tax credit, there should not be any impact on price.

148. The second request is to impose excise duty on set top boxes. I propose to accept the request and levy an excise duty of 16 per cent and, at the same time, reduce the customs duty from 15 per cent to nil. This change will equalize the duty rates on various types of set top boxes.

149. To round off, I would be failing in my duty if I did not raise the excise duty on cigarettes. Hence, I propose to increase the excise duty on cigarettes by about 5 per cent.

150. The bane of excise and customs tariffs is the plethora of exemptions. On the basis of a comprehensive review, I propose to remove many exemptions that were granted through notifications. Broadly, exemptions that are end-use based or have outlived their utility or need certification or give rise to disputes are being rescinded, with only a few exceptions. The exemption for the SSI sector will, however, remain unchanged.

151. We have also identified some more notifications which need to be removed. However, before taking a final view, I propose to put a list of such notifications on the Ministry's website and invite comments.

152. This leaves service tax. In 2005-06, the services sector is estimated to contribute 54 per cent of GDP. Naturally, it should also contribute significantly to the exchequer. Continuing in the direction followed in the last few years, I propose to bring more services under the service tax net. The new services to be covered include ATM operations, maintenance and management; registrars, share transfer agents and bankers to an issue; sale of space or time, other than in the print media, for advertisements; sponsorship of events, other than sports events, by companies; international air travel excluding economy class passengers; container services on rail, excluding the railway freight charges; business support services; auctioneering; recovery agents; ship management services; travel on cruise ships; and public relations management services.

153. I also propose to expand the coverage of certain services now subject to service tax. I do not wish to burden the House with the details which are available in the Budget papers.

154. The leasing and hire purchase industry has faced some difficulty owing to the levy of service tax on all components of payments, including interest. I propose to rectify the anomaly. Accordingly, interest and instalments of the principal amount will be abated in calculating the value of the service.

155. It is my sense that there is a large consensus that the country should move towards a national level Goods and Services Tax (GST) that should be shared between the Centre and the States. I propose that we set April 1, 2010 as the date for introducing GST. World over, goods and services attract the same rate of tax. That is the foundation of a GST. People must get used to the idea of a GST. Hence, we must progressively converge the service tax rate and the CENVAT rate. I propose to take one step this year and increase the service tax rate from 10 per cent to 12 per cent. Let me hasten to add that since service tax paid can be credited against service tax payable or excise duty payable, the net impact will be very small.

Direct Taxes

156. I shall now turn to my proposals on direct taxes.

157. The good news is that there will be no change in the rates of personal income tax or corporate income tax.

158. The other piece of good news is that no new taxes are being imposed.

159. The one-by-six scheme under the Income Tax Act obliging certain categories of persons to file returns will stand abolished.

160. I propose to marginally revise certain tax rates in the quest for equity. While the corporate tax rate is 30 per cent, the rate under Minimum Alternate Tax (MAT) is only 7.5 per cent of book profits. I propose to increase the rate to 10 per cent, which is still only one-third of the normal rate. I also propose to include long-term capital gains arising out of securities in calculating book profits. I have already allowed MAT-paying companies to take credit for MAT over five years. I propose to extend the period to seven years as well as adjust MAT credit while calculating interest liability.

161. The rates for the Securities Transaction Tax (STT) were fixed when prices of securities were much lower. Reflecting the increase in implicit capital gains in securities transactions, I propose an increase of 25 per cent, across the board, on all rates of STT.

162. Section 80IA of the Income Tax Act applies to infrastructure facilities. For developing an industrial park the terminal date is March 31, 2006. I propose to extend the period to March 31, 2009. For the power sector, in view of the ultra mega projects, I propose to extend the date to March 31, 2010.

163. Last year, I recast the provisions relating to savings. Fixed deposits were not included. There is a demand that fixed deposits of certain tenure should qualify for tax exemption. I propose to include investments in fixed deposits in scheduled banks for a term of not less than five years in section 80C of the Income Tax Act. I also propose to remove the limit of Rs. 10,000 in respect of contribution to certain pension funds in section 80CCC, subject to the overall ceiling of Rs. 100,000.

164. I propose to align the definition of open-ended equity-oriented schemes of mutual funds in the Income Tax Act with the definition adopted by SEBI. I also propose to treat open-ended equity-oriented schemes and close-ended equity-oriented schemes on par for the purpose of exemption from dividend distribution tax.

165. I have revisited the exemptions in the Income Tax Act. As a result, I propose to remove the exemption under section 10(23G) which is not relevant when interest rates are moderate.

166. Cooperative banks, like any other bank, are lending institutions and should pay tax on their profits. Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks (PCARDB) stand on a special footing and will continue to be exempt from tax under section 80P of the Income Tax Act. However, I propose to exclude all other cooperative banks from the scope of that section.

167. Section 54EC and section 54ED are tax shelters. I propose to restrict the scope of section 54EC to two institutions, viz., NHAI and REC. For NABARD, SIDBI and NHB, which are banks, we have already opened the route of zero coupon bonds to raise low cost funds. Government will, if needed, provide appropriate support to these institutions to enable them to access resources to fulfil their mandate effectively. I also propose to withdraw the benefit of section 54ED, which has become virtually redundant, with effect from April 1, 2006.

168. The Standing Committee on Finance has expressed concern that many charitable institutions misuse the provisions of the Income Tax Act. I propose to focus on one misuse, namely, receiving anonymous or pseudonymous donations. Accordingly, I propose that anonymous or pseudonymous donations to wholly charitable institutions will be taxed at the highest marginal rate. Such donations to partly religious and partly charitable institutions/trusts will be taxed only if the donation is specifically for an educational or medical purpose. However, I make it clear that such donations to wholly religious institutions and religious trusts will not be covered by the new provision.

169. Members of State Legislatures have complained that their constituency allowances are taxed differently from the constituency allowance received by Members of Parliament. I propose to remove the discrimination and treat them equally.

170. The Permanent Account Number (PAN) of the Department of Income Tax is the critical element in capturing incomes and expenditures. Scrutiny of Annual Information Returns (AIR) on high-value transactions reveals that 60 per cent of the transactions are without quoting PAN. Hence, I propose to take the power to issue PAN *suo motu* in certain cases. I also propose to take the power to direct persons to apply for PAN in certain cases. I propose to notify, in due course, more transactions for which quoting of PAN will be mandatory. I also propose to prescribe a few more transactions to be reported in AIRs.

171. Last year, I introduced two new taxes. The Banking Cash Transaction Tax (BCTT) has turned out to be a boon, not for the modest revenues it brought which was never its purpose, but for the remarkable trails that it has helped establish. To cite just one example, huge cash withdrawals in a bank branch in Chandni Chowk, noticed through the BCTT, led the Department of Income Tax to three entities which were carrying on the business of purchasing demand drafts from traders at a discount and helping the traders to avoid both sales tax and income tax. These entities would deposit the demand drafts in their own accounts and withdraw the cash. In a period of 18 months, they had laundered Rs. 1,500 crore. BCTT has also helped the Department to detect bogus bills, accommodation entries, artificial loss claims and dummy firms. I propose to continue the BCTT for some more time until the AIR system is able to capture all significant financial transactions.

172. Fringe Benefit Tax (FBT) was introduced as a revenue raising measure. FBT can be justified on the principles of horizontal equity and vertical equity. Nevertheless, I have reviewed it with an open mind. I have also taken on board the views expressed by the apex chambers of commerce. I propose to make the following changes in chapter XII-H of the Income Tax Act:

- Value the benefit in the form of 'tour and travel' at 5 per cent instead of 20 per cent;
- Value the benefit in the form of 'hospitality' and 'use of hotel boarding and lodging facilities', in the case of airline companies and shipping industry, at 5 per cent instead of 20 per cent;
- Exclude the expenses on free samples of medicines and of medical equipment distributed to doctors;
- Exclude the expenses incurred on brand ambassador and celebrity endorsement; and
- Prescribe a threshold of Rs.100,000 under section 115WB(1)(c) so that only a contribution by an employer to an approved superannuation fund in excess of Rs.100,000 per year per employee will attract FBT. Under section 80C there is already an exemption up to Rs.100,000 for contribution by an employee to an approved superannuation fund. Honourable Members will note that, under these two provisions, there can now be a tax-exempt contribution up to Rs.200,000 per year for the benefit of an employee. This allowance, I believe, is generous enough in the case of an overwhelming majority of employees.

With these changes, I am confident that the debate on FBT will draw to a close. Let me remind everyone concerned once again that FBT is justified on the principle of equity.

Modernizing Tax Administration

173. I am glad to inform the House that technology is being increasingly employed to modernize tax administration. The Departments of Income Tax and Customs and Central Excise will undergo Business Process Reengineering (BPR). Nationwide networks will connect 745 income tax offices in 510 cities and 550 customs and central excise offices in 245 cities, creating national databases. National data centres, data warehousing facilities and disaster recovery sites are being set up. Jurisdiction-free filing of returns, online tracking of status of accounts and refunds of income tax will be possible. Introduction of a risk management system and Electronic Data Interchange (EDI) in the Customs Department will reduce dwell time for cargo. E-payments of customs and excise duties will be possible. Both Departments will have fully computerised networks by end 2006.

174. Our Government's two Budgets have seen many innovations – the Gender Budget, the Outcome Budget etc. Today, I place before the House another innovation – a statement on revenue foregone, known worldwide as tax expenditure statement. This statement captures the departures from the normal tax regime. This exercise is a first attempt that will be fine tuned in the years to come.

VAT and CST

175. The House is aware that most States have implemented VAT with effect from April 1, 2005, and the unanimous opinion is that VAT has been a resounding success. I hope that the non-VAT States will soon join the mainstream, because the next stage of reform depends on all States implementing VAT. The Empowered Committee of State Finance Ministers has recommended that Central Sales Tax (CST) be phased out, and have requested the Centre to compensate them for the expected loss of revenue. Government has proposed that the loss of revenue may be compensated through monetary and non-monetary measures which, taken together, will ensure that the States' revenues remain buoyant. Once the Empowered Committee and the Government reach an agreement, I shall return to the House with firm proposals, including legislative changes and a supplementary demand.

176. In the meanwhile, there is an urgent matter connected with CST and VAT which has to be attended to. It has become imperative to moderate the price of Liquified Petroleum Gas (LPG) for domestic use. States are taxing LPG (domestic) at high rates. They should also bear a portion of the burden of high prices of petroleum products. Hence, in order to moderate the price of LPG (domestic), I propose to include LPG (domestic) in the list of 'declared goods' under the CST Act.

177. My tax proposals on direct taxes are estimated to yield a gain of about Rs.4,000 crore. On the indirect taxes side, the gain is estimated at Rs.2,000 crore.

XV CONCLUSION

178. Mr. Speaker, Sir, I believe that the world has recognized the potential of India. It is now for us, the generation to which has been given the privilege of carrying the torch, to rediscover the greatness of this country and the potential of its people. The young people of India are building castles, it may appear that those castles are in the air, but as Henry David Thoreau said: "If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them." It is our duty to put the foundations on which the young can build their castles. The UPA Government has pledged itself to that task.

179. Over a hundred years ago, a restless young man in his quest for the core of all spirituality admonished his fellow men in the following words: "We reap what we sow. We are the makers of our own fate. The wind is blowing; those vessels whose sails are unfurled catch it, and go forward on their way, but those which have their sails furled do not catch the wind. Is that the fault of the wind?..... We make our own destiny." Those are the immortal words of Swami Vivekananda. Let us believe in our destiny, let us make our future.

180. Sir, with these words, I commend the Budget to the House.

L. M. VAS, Jt. Secy.